वर्ष 13 • अंक 41 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

बुधवार 8 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

सोने की कीमतों ने लगाई छलांग

निर्मला सीतारमण पृष्ठ 4

राज्यों को बकाया जीएसटी मुआवजा देगा केंद्र

डॉलर रु. 75.60 ▼ 0.60 रुपये | यूरो रु. 82.20 अपरिवर्तित | सोना (10ग्राम) रु. 44,700 ▲ 940 रुपये | सेंसेक्स 30067.20 ▲ 2476.30 | निफ्टी 8792.20 ▲ 708.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 8875.80 ▲ 83.60 | ब्रेंट क्रूड 28.90 डॉलर ▲ 0.80 डॉलर

एक नज़र

लॉकडाउन हटाने पर बढ़ेगा खतरा : आईसीएमआर

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने अनुमान लगाया है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो कोरोनावायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस बीच कोविड-19 से कुल 4,421 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर का यह अध्ययन ऐसे वक्त पर आया है जब विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकार से लॉकडाउन अवधि 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि अगर 75 फीसदी लॉकडाउन हटा लिया जाता है, तब एक संक्रमित व्यक्ति 2.5 लोगों को संक्रमित करेगा। पृष्ठ 8

एसबीआई ने मानक ब्याज दर में की कटौती

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को 10 अप्रैल से सभी अवधि के ऋणों पर कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.35 फीसदी कटौती करने की घोषणा की। साथ ही बैंक ने बचत खाता जमा पर भी ब्याज दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 2.75 फीसदी कर दिया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि एमसीएलआर में कटौती के बाद एक वर्ष की अवधि के ऋण पर ब्याज दर 7.75 फीसदी से घटकर 7.40 फीसदी वार्षिक हो जाएगी। अधिकांश खुदरा ऋणों के लिए एक वर्ष की अवधि के कर्ज पर दर को पैमाना माना जाता है। बैंक ने कहा कि इससे 30 वर्ष की अवधि वाले आवास ऋण की मासिक किस्त प्रति एक लाख रुपये कर्ज पर 24 रुपये कम हो जाएगी। इसी के साथ बैंक ने बचत खातों की जमा पर ब्याज दर को 0.25 फीसदी घटाकर 2.75 फीसदी करने की भी घोषणा की।

व्हाट्सऐप ने किया मेसेज फॉरवर्ड नियमों में बदलाव

व्हाट्सऐप ने कोरोना संकट के बीच फर्जी खबरें और जानकारियां फैलने की समस्या से निपटने के लिए संदेश फॉरवर्ड (साझा करने) के नियमों में बदलाव किया है और अब ज्यादा फॉरवर्ड होने वाले संदेशों को एक बार में एक जगह भेजने की सीमा लगा दी है।अभी तक यह सीमा सीमा पांच लोगों या समूहों तक की थी। फेसबुक के स्वामित्व वाली मेसेंजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हम नया फीचर पेश कर रहे हैं। इससे अब संदेशों को एक बार में केवल एक चैट में फॉरवर्ड किया जा सकेगा। हमने संदेशों के फॉरवर्ड होने की संख्या में उल्लेखनीय बढ़त देखी है। इस नए फीचर से उपयोक्ता भ्रामक जानकारियों को फैलने से रोकने में योगदान कर सकते हैं। पृष्ठ 8

कोरोना के चलते आईसीयू में भर्ती हुए बोरिस जॉनसन

कोरोनावायरस के लक्षणों से निजात न मिलने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें सघन निगरानी कक्ष (आईसीयू) में रखा गया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने यह जानकारी दी। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सोमवार को आईसीयू में भर्ती कराए जाने के बाद 55 वर्षीय जॉनसन ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब को फिलहाल उनकी जगह लेने को कहा है। डाउनिंग स्ट्रीट ने आईसीयू में जॉनसन को भेजे जाने को एहितयातन उठाया कदम बताया है क्योंकि स्वस्थ होने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखे जाने की जरूरत पड़ सकती है। दुनिया के कई देशों के प्रमुखों ने जॉनसन के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की।

व्यापार गोष्ठी

कोरोना की मार से कैसे बचें छोटे उद्योग?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाना सही कदम होगा

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या दवा निर्यात से पाबंदी हटाना उचित होगा? हां **50.00%** नहीं **50.00%**

लॉकडाउन बढ़ाने का दबाव

कई राज्यों ने केंद्र सरकार से 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने को कहा

आदिति फडणीस
नई दिल्ली, 7 अप्रैल

लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान के बावजूद केंद्र सरकार ने आज संकेत दिया कि उसे 15 अप्रैल को इसे हटाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। कई राज्यों ने स्पष्ट कहा है कि वे बाहर से आने वाले लोगों के कारण नए क्षेत्रों में कोविड-9 फैलने से स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ने वाले दबाव से निपटने में सक्षम नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर बुधवार को विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक होनी है। माना जा रहा है कि मोदी इस बैठक में लॉकडाउन को कुछ हफ्ते और बढ़ाने की बात कह सकते हैं। संभवत: इसे 1 जून तक बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अब इसे वापस लिया जा सकता है क्योंकि इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है। लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में अंतिम फैसले की घोषणा 10 अप्रैल के आसपास की जा सकती है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ अगले दौर का विचार विमर्श करेंगे।

केंद्र ने संकेत दिया कि उसे उन कंपनियों और प्रतिष्ठानों से हमदर्दी है जो लॉकडाउन खत्म करने की मांग कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकारें लॉकडाउन के आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही हैं। उदारहण के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का कहना है कि उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही भारी दबाव में हैं। सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए जिला अस्पतालों में 10 हजार आइसोलेशन बिस्तरों की पहचान की है और अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो इस संख्या को दोगुना करने के लिए एक आपात योजना बनाई गई है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों के आसपास के होटल, लॉज और हॉस्टल में व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि निजी सुविधाओं में ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जिनकी जांच पॉजिटिव है लेकिन जिनमें इसके लक्षण नहीं हैं। इससे पहले सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा था कि लॉकडाउन अगर राज्य में मरीजों की संख्या में इजाफा जारी रहा तो लॉकडाउन बढ़ाया सकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूरी तरह कोरोनावायरस से मुक्त होने तक लॉकडाउन रह सकता है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के बाद राज्यों के बीच अंतरराज्यीय परिवहन को बहाल करने का फैसला सोच समझकर लिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं। लेकिन इसे अचानक हटाया गया तो इससे कोविड-19 के मामलों में तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते हैं कि लॉकडाउन कब हटाया जाएगा। लेकिन एक बार यह हट गया तो दूसरी समस्या पैदा हो सकती है। परिवहन व्यवस्था बहाल होने से दूसरे राज्यों में फंसे लोग आने लगेंगे जिससे अफरातफरी की स्थिति पैदा हो जाएगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से कहा था कि केंद्र को बिना किसी झिझक के लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की जान अर्थव्यवस्था से जरूरी है।

- 10 अप्रैल तक इस बारे में हो सकता है कोई निर्णय
- राज्यों ने कहा, अचानक लॉकडाउन हटने से होगी अफरातफरी
- कुछ राज्यों में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की
- प्रधानमंत्री की विपक्ष के नेताओं के साथ बुधवार को होगी बैठक

कोरोना अपडेट

भारत
कुल 4,789
सक्रिय मामले 4,312
ठीक हुए 352
मौत 124

विश्व
कुल 13,50,00
मौत 75,500

नोट : कुल मामलों में 1 विदेशी भी शामिल। आंकड़े भारतीय समयानुसार 8 बजे तक के स्रोत : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जोंस हॉकिंग कोरोनावायरस रिसोर्स सेंटर

तंगहाल राज्यों ने महंगी दर पर जुटाई रकम

अनूप राय
मुंबई, 7 अप्रैल

- लॉकडाउन के कारण बाजार में बॉन्ड खरीदार कम होने से आ रही मुश्किल
- राज्यों ने मंगलवार को महंगी दरों पर जुटाए 32,560 करोड़ रुपये
- सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 150 से 200 आधार अंक ज्यादा चुकाना पड़ा

कोरोनावायरस से पैदा हुए हालात और विदेशी निवेशकों के हाथ समेटने के बाद रकम जुटाने के लिए राज्यों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। राज्य सरकारों ने मंगलवार को बॉन्ड बाजार से करीब 32,560 करोड रुपये जरूर जुटाए, लेकिन उन्हें यह सौदा काफी महंगा पड़ा। दूसरी तरफ आर्थिक सुस्ती के बीच बाजार में कारोबारी घंटे कम होने के बाद अपने पास अधिक से अधिक नकदी रखने के लिए निवेशक नकारात्मक बोली लगाने की रणनीति आजमा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे जान बूझकर बॉन्ड के लिए काफी कम कीमतें दे रहे हैं। राज्यों एवं केंद्र सरकार की तरफ से भारी उधारी देखते हुए घरेलू निवेशकों ने बॉन्ड बाजार में समतुल्य सरकारी बॉन्ड के मुकाबले 140 से 200 आधार अंत तक अधिक प्रतिफल की मांग की। राज्यों के पास निवेशकों की मांग पूरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उदाहरण के लिए केरल ने 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड पर 8.96 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया। इतनी ही अवधि के सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल 6.92 प्रतिशत दर्ज की गईं। सामान्य हालात में सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में दूसरे बॉन्ड पर प्रतिफल में 60 से 70 आधार अंक से अधिक का अंतर नहीं रहता है।

उधारी कार्यक्रम के अनुसार देश के 19 राज्यों ने 37,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना तैयार की थी, लेकिन वे 32,560 करोड़ रुपये ही जुटा पाए। बॉन्ड बाजार में मौजूदा कारोबार पर एक बैंक के ट्रेजरी प्रमुख ने कहा, 'बाजार में बॉन्ड की बिल्कुल मांग नहीं है। लिहाजा, बैंकों ने इस अंदाज में बोली लगाई कि रकम जुटाने वाले तैयार नहीं हो पाए। हालांकि राज्यों को विवशता में बोलियां स्वीकार करनी पडीं।'

अधिकारी ने आगाह किया कि ऐसा न हो कि बॉन्ड बाजार में मौजूदा कारोबारी ढर्रा अपवाद न होकर सामान्य चलन का हिस्सा बन जाए। ऐसा हुआ तो आने वाले समय में केंद्र सरकार को भी रकम जुटाने के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। अधिकारी के अनुसार द्वितीयक बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के जरिये बॉन्ड खरीदने की स्थिति में ही सरकार की नैया पार होगी। एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक में परिसंपत्ति-देनदारी प्रबंधन प्रमुख देवेंद्र दास ने कहा, 'राज्यों के बॉन्ड का बाजार में कारोबार नहीं होता है, इसलिए मांग कम है। बाजार में कारोबारी घंटे भी कम कर दिए हैं और इससे भी मांग के बारे में पुख्ता तौर पर कुड कह पाना मुमकिन नहीं लग रहा है। कुल मिलाकर बाजार आरबीआई से मदद की मांग कर रहा है।'

मंगलवार को बॉन्ड और मुद्रा बाजार 2 बजे बंद हो गया है, जो अमूमन 5 बजे शाम तक खुले रहते हैं। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 17 अप्रैल तक बाजार में सुबह 10 बजे से लेकर दोहपर 2 बजे तक कारोबार होगा। फर्स्ट रैंड बैंक के ट्रेजरी प्रमुख हरिहर कृष्णमूर्ति ने कहा, 'इस समय ज्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे है, इसलिए कम लोग खरीदारी के लिए आगे आ रहे हैं। सावधि ऋण भुगतान तीन महीने तक टालने के आरबीआई के निदेश के बाद बैंकों को नकदी के मामले में सतर्क रहना होगा। पहले उन्होंने जिस सीमा तक नकदी आने का अनुमान लगाया था वैसा नहीं होता दिख रहा है।'

चालू तिमाही के लिए राज्यों ने 1.29 लाख करोड़ और केंद्र ने 21,0000 करोड़ रुपये तक उधार लेने की योजना तैयार की है, लेकिन आरबीआई ने अब तक इसमें ओएमओ के जरिये सहयोग नहीं किया है।

सेंसेक्स में 2,476 अंक की उछाल

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 7 अप्रैल

2009 से एक दिन में आई पांच बड़ी उछाल

	सेंसेक्स	तेजी (%)*
18 मई, '09	14,284	17.34
07अप्रैल, '20	30,067	8.97
25 मार्च, '20	28,536	6.98
04 मई, '09	12,135	6.41
20 मार्च, '20	29,916	5.75

*एक दिन में आई तेजी

बाजार पूंजीकरण बढ़ा

~108 लाख करोड़
3 अप्रैल
~116 लाख करोड़
7 अप्रैल
~8 लाख करोड़

कोरोनावायरस के फैलने की रफ्तार कम होने की उम्मीद से घरेलू बाजार ने आज करीब 9 फीसदी की लंबी छलांग लगाई। दुनिया के अधिकांश बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों से उत्साह बढ़ाने वाले संकेत मिले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके देश में अब इसका प्रकोप चरम स्तर को पार कर गया है। इससे निवेशकों की धारणा को बल मिला। अमेरिका के बाजारों में सोमवार को 8 फीसदी की तेजी देखी गई थी और आज भी इसमें बढ़त के संकेत हैं।

भारतीय बाजार छुट्टी के कारण सोमवार को बंद थे लेकिन आज उन्होंने इसकी भरपाई कर ली। 11 साल में भारतीय बाजारों की यह एक दिन में सबसे बड़ी तेजी है।

सेंसेक्स 2,476 अंक चढ़कर 30,067 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 708 अंक बढ़कर 8,792 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों की मई 2009 के बाद यह एक दिन में सबसे बड़ी छलांग है। इसके पीछे मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा जमकर की गई लिवाली रही। कई महीनों बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विशुद्ध लिवाल रहे यानी उन्होंने बिकवाली से अधिक लिवाली की।

कुल मिलाकर उन्होंने 740 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। हालांकि यह रकम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि यह आंकड़ा धारणा को मजबूत करने वाला है। मार्च में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने रिकॉर्ड 62,000 करोड़ रुपये भारतीय शेयरों से निकाले।

विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ निवेशकों ने इसलिए जमकर लिवाली की क्योंकि लॉकडाउन के उपाय कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने में कारगर रहे हैं। बीएनपी पारिबा इंडिया के इक्विटी प्रमुख अभिराम एलेस्वरापू ने कहा, 'कुछ दिन पहले तक बाजारों की नजर रोज आने वाले नए मामलों पर थी लेकिन अब वे अब उनका ध्यान प्रतिदिन आने वाले नए मामलों की दर पर है जिसमें गिरावट आ रही है।'

हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और कोरोनावायरस महामारी से निपटने की दोहरी चुनौती है।

एचसीक्यू के सीमित निर्यात की अनुमति

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से दबाव बढ़ाए जाने के बाद भारत ने आज कहा कि वह पड़ोसी देशों और कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के आंशिक निर्यात की अनुमति देगी। समझा जाता है कि अमेरिका के अलावा ब्राजील और स्वीडन ने भी भारत से इस दवा के निर्यात का अनुरोध किया है। कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली इस दवा की अप्रत्याशित मांग के बीच दवा विनिर्माताओं का कहना है कि इससे गठिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज जो इसका नियमित सेवन करते हैं, उन्हें दवा मिलने में मुश्किल आ सकती है। इसके साथ ही इसका कई अन्य बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल को लाइसेंसी दवा की श्रेणी में बनाए रखा जाएगा और उनकी मांग पर नजर रखी जाएगी।

हालांकि दवा के स्टॉक को देखते हुए दवा कंपनियों को इसके निर्यात की अनुमति दी जा सकती है। वैसे खबर लिखे जाने तक विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।

भारत ने कहा कि मानवीय आधार पर पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की समुचित मात्रा में उन पड़ोसी देशों को निर्यात करने का निर्णय किया गया है, जहां इसका ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। पृष्ठ 8

थमे रेल के पहिए.. स्टेशनों पर पसरी खामोशी

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 7 अप्रैल

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंजनों की सीटी की आवाज, लोगों की भारी भीड़ और 'यात्रीगण कृपया ध्यान दें' की उद्घोषणा की जगह पिछले दो हफ्ते से अजीब सी खामोशी है। कभी-कभी मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर इस खामोशी को तोड़ती है।

स्टेशन के कर्मचारियों, रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) और अपनी आजीविका के लिए स्टेशन पर निर्भर ज्यादातर लोगों के लिए 21 दिन का यह लॉकडाउन ऐसा पहला अनुभव है, जो उन्होंने वर्ष 1974 में रेलवे की 20 दिन की हड़ताल के बाद कभी नहीं देखा। वर्ष 1974 में भी ट्रेनों का परिचालन थम गया था।

स्टेशन के पहाड़गंज की तरफ के प्रवेश द्वार पर दीपक कुमार और चार अन्य सफाईकर्मी अपने रोजाना के काम में व्यस्त थे। कुमार ने कहा, 'हमने नई दिल्ली स्टेशन का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। लेकिन रेलवे के कर्मचारी आ रहे हैं, इसलिए हमें भी अपना तय काम करना पड़ रहा है। सफाईकर्मियों के नजरिये से गंदगी कम है लेकिन स्टेशन की जीवंतता भी खत्म हो चुकी है।'

लॉकडाउन के नियमों के कारण केवल 50 फीसदी सफाईकर्मी ही काम पर आ रहे हैं। वे काफी दूर से आते हैं। इसमें भी उन्हें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें पुलिसकर्मी रास्ते में रोक लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल ट्रेनों से आते-जाते थे लेकिन ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लॉकडाउन की वजह से वीरान पड़ा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।

अजमेरी गेट की तरफ से 16 प्लेटफॉर्म पार करने पर भी हवा में वही खामोशी और अनिश्चितता महसूस होती है। एक पोस्टर पर लिखा है, 'मैं आपके लिए काम पर लगा हूं, इसलिए आप हमारे लिए घर में रहें। आओ कोरोना से मिलकर लड़ें।' इसकी तरफ इशारा करते हुए स्टेशन प्रबंधक संजय गोयल ने कहा, 'इस स्टेशन पर 4,500 से अधिक लोग काम करते हैं। लेकिन अब यह संख्या महज कुछ सौ रह गई है। आम दिनों में 354 ट्रेन नई दिल्ली से होकर गुजरती हैं, जिनकी संख्या घटकर 45-50 रह गई है, जो सभी मालगाड़ियां हैं।' वर्ष 2019 में इस स्टेशन पर लोगों की दैनिक औसत आवाजाही पांच लाख थी। भारत के इस दूसरे सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर केवल रेलवे कर्मचारी ही नजर आते हैं, वह भी इक्के-दुक्के।

भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान रोजाना करीब 45,000 से 50,000 मालढुलाई डिब्बों का प्रबंधन कर रही है। गोयल ने कहा, 'हम जिस माल की मुख्य रूप से ढुलाई कर रहे हैं, उसमें अनाज, कोयला, इस्पात और पेट्रोलियम जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

सरकार यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है कि आम आदमी के उपभोग के लिए चीनी नमक और खाद्य तेल जैसी चीजों की कमी न हो।' उदाहरण के लिए रेलवे ने 23 मार्च से 4 अप्रैल तक की 13 दिन की अवधि के दौरान ही चीनी के 1,342 वैगन, नमक के 958 और खाद्य तेल के 378 वैगन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए हैं। (शेष पृष्ठ 8 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

कैडिला हेल्थकेयर

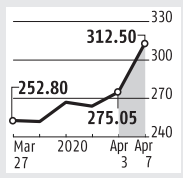

परफेनाजाइन टैबलेट के विपणन के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी

₹ 275.05 पिछला बंद भाव
₹ 312.50 आज का बंद भाव

▲ 13.62 %

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा

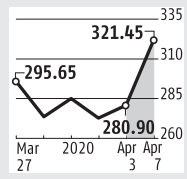

एसऐंडपी बीएसई वाहन सूचकांक में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 280.90 पिछला बंद भाव
₹ 321.45 आज का बंद भाव

▲ 14.44 %

लार्सन ऐंड टुब्रो

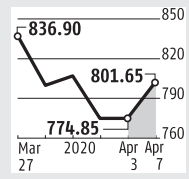

सेना से उन्नत आईटी समर्थ नेटवर्क के लिए मिला बड़ा ऑर्डर

₹ 774.85 पिछला बंद भाव
₹ 801.65 आज का बंद भाव

▲ 3.46 %

आईनॉक्स लेजर

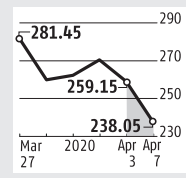

लंबे समय तक बंद रहने से क्रेडिट प्रोफाइल पर दिखेगा उल्लेखनीय प्रभाव

₹ 259.15 पिछला बंद भाव
₹ 238.05 आज का बंद भाव

▼ 8.14 %

इंडसइंड बैंक

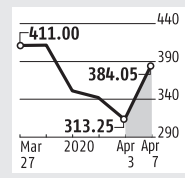

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 313.25 पिछला बंद भाव
₹ 384.05 आज का बंद भाव

▲ 22.60 %

संक्षेप में

इंडिगो, स्पाइसजेट की राहत उड़ानें

प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा है कि वह चिकित्सा उपकरणों एवं खाद्य वस्तुओं के परिवहन के लिए 30 राहत उड़ानों का संचालन कर रही है। इसी प्रकार स्पाइसजेट ने अपने बोइंग 737 विमाना के भीतर यात्री केबिन में कार्गो की ढुलाई शुरू कर दी है। स्पाइसजेट ने मंगलवार को 11 टन आवश्यक वस्तुओं को यात्री केबिन में रखकर दिल्ली से चेन्नई के लिए उड़ान भरी। सीटों को ढकने के लिए विशेष सीट कवर का इस्तेमाल किया गया और कार्गो को सुरक्षित रखा गया। नागर विमानन मंत्रालय के उड़ान कार्यक्रम के तहत देश भर में फिलहाल 152 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। इनके जरिये देश के विभिन्न भागों में चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। *बीएस*

इंडसइंड बैंक की जमाएं 7 फीसदी घटी

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने कहा कि येस बैंक संकट के कारण उसके यहां निकासी बढ़ने से मार्च तिमाही में उसकी जमाएं 7 फीसदी घट गईं। बैंक ने एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा कि मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान उसकी जमाएं घटकर 2,02,303 करोड़ रुपये रह गईं, जो इससे पिछली तिमाही में 2,16,713 करोड़ रुपये थीं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में बैंक का चालू खाता-बचत खाता (सीएएसए) अनुपात तीसरी तिमाही के 42.4 फीसदी से घटकर 40.5 फीसदी रह गया। हिंदुजा समूह द्वारा प्रवर्तित इंडसइंड बैंक की वित्तीय सेहत को लेकर चिंता के चलते बैंक से भारी मात्रा में जमाएं निकाली गई हैं। *भाषा*

उत्तम गैल्वा ने की भुगतान में चूक

आर्सेलरमित्तल, एसबीआई हैं उत्तम गैल्वा के लेनदार, 664 करोड़ रुपये की अदायगी थी

देव चटर्जी
मुंबई, 7 अप्रैल

कोरोनावायरस महामारी के कारण हुई बंदी का असर भारतीय कंपनियों पर पड़ना शुरू हो गया है और उत्तम गैल्वा स्टील्स लिमिटेड ने लेनदारों को 664 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की है। सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के अलावा आर्सेलरमित्तल इस कंपनी के अग्रणी लेनदारों में से एक है।

पिछले महीने घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के ऐलान के बाद कंपनी ने अपने संयंत्र और परिचालन बंद कर दिए। कंपनी ने कहा कि उसके ऊपर लेनदारों का 1,008 करोड़ रुपये बकाया है।

कंपनी के एक सूत्र ने कहा, इस डिफॉल्ट की प्रकृति तकनीकी है और इसके लिए उन्होंने मौजूदा लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। कंपनी को अपना कामकाज बंद करना पड़ा जब मौजूदा लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई। कंपनी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय स्टेट बैंक, ओरियंटल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और विजया बैंक ने कंपनी को कर्ज दे रखा है। उत्तम गैल्वा के कर्ज का बड़ा हिस्सा आर्सेलरमित्तल

- लॉकडाउन के बाद कंपनी ने संयंत्र और परिचालन बंद कर दिया
- कंपनी ने कहा कि उसके ऊपर लेनदारों का 1,008 करोड़ रुपये बकाया है
- इस डिफॉल्ट की प्रकृति तकनीकी है और इसके लिए कंपनी ने मौजूदा लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया है

ने सार्वजनिक बैंकों से अधिग्रहीत कर लिया था जब उसने साल 2018 में एस्सार स्टील के लिए बोली लगाई और बाद में लंबी कानूनी संघर्ष के बाद कंपनी हासिल की।

आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इस कर्ज को अधिग्रहीत किया था, जिसने उत्तम गैल्वा के सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को 4,922 करोड़ रुपये चुकाए थे, जो 30 सितंबर 2018 तक का मूलधन और उस पर 17 अक्टूबर 2018 तक बकाया ब्याज था। बाद में बकाया मूलधन आर्सेलरमित्तल इंडिया को असाइन किया गया और बाकी कर्ज मौजूदा सरकारी बैंकों के साथ बना रहा। इसी तरह बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सुविधा आंशिक तौर पर सिटी बैंक की लंदन शाखा को असाइन किया गया और आर्सेलरमित्तल, लग्जमबर्ग ने 13.6 करोड़ डॉलर चुकाए।

उत्तम गैल्वा का स्वामित्व हालांकि मिगलानी परिवार के पास बना रहा, जिसने 7 फरवरी 2018 को कंपनी में आर्सेलरमित्तल की 29 फीसदी हिस्सेदारी एक रुरुपये में अधिग्रहीत की थी और यह काम एस्सार स्टील के लिए बोली लगाने से ठीक पहले हुआ था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में आर्सेलरमित्तल से कहा कि अगर वह एस्सार की बोली का पात्र बनना चाहती है तो वह उत्तम गैल्वा के बकाए का भुगतान करे। कर्ज के अधिग्रहण के बावजूद उत्तम गैल्वा का वित्तीय प्रदर्शन नहीं सुधरा क्योंकि आर्थिक सुस्ती आई और वह लगातार कम राजस्व और उच्च नुकसान दर्ज करती रही। दिसंबर 2019 की तिमाही में उसका राजस्व 147 करोड़ रुपये रहा जबकि नुकसान 273 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2019 में उसका राजस्व 556 करोड़ रुपये था जबकि 2,126 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान।

आर्सेलरमित्तल के भुगतान के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालिया याचिका दाखिल करने वाले एसबीआई ने 1 नवंबर 2018 को याचिका वापस ले ली, जिससे कंपनी को राहत मिली।

वित्त वर्ष 2019 की सालाना रिपोर्ट में कंपनी ने चेतावानी दी थी कि मौजूदा परिचालन से मिलने वाली नकदी मूलधन व ब्याज भुगतान जैसे तय खर्च के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि बकाया कर्ज एनपीए न बन जाए, इसके लिए कंपनी ने आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अंतर-कंपनी जमाओं के जरिए ली गई रकम का भुगतान चुकाए जाने की तारीख से 90 दिन पहले की।

कारोबारी रणनीति में जुटीं यात्रा कंपनियां

अनीश फडणीस
मुंबई, 7 अप्रैल

यात्रा कंपनियां नई कारोबारी योजना पर काम कर रही हैं। इसके तहत वे ग्राहकों के साथ जुड़ने के तौर-तरीके पर विचार करने के अलावा अपने कर्मचारियों को कोविड-19 के बाद के कारोबारी माहौल के अनुकूल बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं।

कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के उद्देश्य से दुनिया भर में यात्रा पर प्रतिबंध और कर्फ्यू लगाए जाने के कारण यात्रा उद्योग को जबरदस्त झटका लगा है। यात्रा उद्योग को फिलहाल अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है और यह भी मालूम नहीं है कि यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध कब खत्म होंगे।

थॉमस कुक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक माधवन मेनन ने कहा, 'फिलहाल हमारी प्राथमिकता कंपनी और कर्मचारियों को बचाना है।' मेनन ने कहा, 'हम यह देखने के लिए कई परियोजनाएं चला रहे हैं कि हमारे उत्पादों, प्रौद्योगिकी, ग्राहक संबंध और कार्यस्थल में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है।' इस टूर ऑपरेटर ने फरवरी में अनुमान जाहिर किया था कि उसके तिमाही नतीजों पर कोरोनावायरस संकट का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्टिक ट्रैवल ग्रुप की निदेशक ईशा गोयल ने कहा, 'हम बिक्री कौशल कार्यशालाओं और ऑनलाइन उत्पाद पेशकश के साथ कोविड बाद के बाजार के लिए अपना कार्यबल तैयार कर रहे हैं। हम अपनी बिक्री टीम के साथ लगातार संपर्क के जरिये यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल हों और नए अवसरों को भुनाने के लिए तैयार रहें।' वॉव हॉलिडेज के संस्थापक चेयरमैन माधव पई ने कहा, 'यात्रा पर हर तरह से प्रतिबंध को देखते हुए ऐसा लगता है कि दूसरे देश के पर्यटन के लिए यह साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।'

यात्रा डॉट कॉम के सह-संस्थापक एवं सीईओ ध्रुव श्रृंगी ने कहा, 'यात्रा उद्योग काफी कठिन दौर से गुजर रहा है। इस समय अधिकतर कंपनियां लागत में कटौती और नकदी बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वित्त वर्ष 2020 के लिए कोई बोनस अथवा अगले वर्ष के लिए वेतन वृद्धि की तरह विपणन अभियान को भी फिलहाल टाला जा रहा है। इस उद्योग में सुधार धीरे-धीरे होगा। यात्रा विशेषकर अंतरराष्ट्रीय यात्रा कारोबार को पटरी पर लौटने में एक-दो तिमाहियों से अधिक समय लगेगा।'

वर्ल्ड ट्रैवल ऐंड टूरिज्म काउंसिल ने पिछले महीने कहा था कि कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के कारण यात्रा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 5 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं।

मार्च में कंपनियों की निवेशकों के साथ बैठक में रही तेजी

सचिन मामबटा
मुंबई, 7 अप्रैल

कोरोनावायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारणअर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बीच कंपनियां बैठकों, फोन कॉल और प्रस्तुतियों के जरिये निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बातचीत करने में काफी तत्परता दिखा रही हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में मार्च में कंपनियों द्वारा निवेशकों और विश्लेषकों के साथ सबसे अधिक बैठकें हुईं।

एनएसई इन्फोबेस डॉट कॉम के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2019 में निवेशक आउटरीच कार्यक्रमों की कुल संख्या 2,609 थी जो बढ़कर मार्च 2020 में 2,728 हो गई। कंपनी प्रशासन संबंधी मुद्दों पर सलाह देने और कंपनी के निर्णयों पर मतदान में निवेशकों की मदद करने वाली फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया (आईआईएएस) के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक अमित टंडन ने कहा कि निवेशक परिचालन बंद होने, उसकी अवधि और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों पर जानकारी हासिल करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी और इसलिए तमाम सवाल पैदा होने लगे। उन्होंने कहा, 'आप जो देख रहे हैं वह बिल्कुल अप्रत्याशित है।' कोविड-19 ने चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन और फ्रांस सहित तमाम देशों को प्रभावित किया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में 13 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इस महामारी के कारण हुई मौतों की संख्या 75,000 से अधिक हो चुकी है। इससे भारत सहित तमाम प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं।

एनएसईइन्फोबेस डॉट कॉम का प्रबंधन करने वाली फर्म प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दीया के अनुसार, एक अन्य कारक येस बैंक को लेकर हो सकता है। इसके कारण भी मार्च के आरंभ में बैठकों की संख्या में तेजी हो सकती है।

मझोली आईटी कंपनियों के प्रवर्तकों ने बढ़ाई हिस्सेदारी

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 7 अप्रैल

पिछले एक पखवाड़े के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आईटी सेवा कंपनियों के शेयरों को जबरदस्त झटका लगा है। इसे देखते हुए कुछ मझोली आईटी सेवा कंपनियों के प्रवर्तकों ने पुनर्खरीद के जरिये कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

बेंगलूरु की आईटी सेवा कंपनी माइंडट्री के प्रवर्तक एलऐंडटी ग्रुप ने इस दौरान खुले बाजार से करीब 58 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर कंपनी में 0.4 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पिछले एक महीने के दौरान माइंडट्री के शेयर मूल्य में करीब 22.78 फीसदी की गिरावट आई है। पुणे की कंपनी जेंसर टेक्नोलॉजिज के प्रवर्तक आरपीजी ग्रुप ने पिछले एक पखवाड़े के दौरान खुले बाजार से करीब 11 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। जेंसर टेक्नोलॉजिज के शेयर में पिछले एक महीने के दौरान करीब 28.70 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। निजी इक्विटी निवेशक और एमफैसिस के बहुलांश हिस्सेदार ब्लैकस्टोन ने 17 से 20 मार्च के दौरान करीब 525 करोड़ रुपये में 74.8 लाख शेयर खरीदकर बेंगलूरु की इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 4 फीसदी बढ़ा ली।

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज के प्रवर्तकों ने शेयर मूल्य में गिरावट के बीच हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी के प्रवर्तकों ने मार्च के पहले सप्ताह से अब तक करीब 8 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग सेवा कंपनी ऐक्सिसकैडेस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिज और क्विक हील टेक्नोलॉजिज के प्रवर्तकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

आईटी आउटसोर्सिंग सलाहकार और पारीख कंसल्टिंग के संस्थापक पारीख जैन ने कहा, 'इससे (प्रवर्तकों द्वारा शेयर खरीदारी से) पता चलता है कि निकट भविष्य में वृद्धि को लेकर प्रवर्तकों को कंपनी पर भरोसा है।'

सरकार ने विमानन कंपनियों से मांगी टिकट रिफंड की जानकारी

अनीश फडणीश
मुंबई, 7 अप्रैल

केंद्र सरकार ने इंटरनैशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) को विमानन कंपनियों के पास आए टिकट रिफंड संबंधी दावों के विवरण साझा करने के लिए कहा है। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएएफआई) ने अपने सदस्यों के साथ एक संवाद में कहा कि नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खारोला ने रविवार को ट्रैवल एजेंटों और आयटा प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉल के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी परिवहन विभाग ने विमानन कंपनियों को ऐसे यात्रियों को पूरी राशि वापिस करने का आदेश दिया है, जुनकी हवाई यात्रा कोरोनावायरस के चलते रद्द कर दी गई। हालांकि भारत सरकार के इस संबंध में विमानन कंपनियों को सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की है।

इस बीच, कई ट्रैवल एजेंटों ने रिफंड प्रक्रिया में देरी की शिकायत की है क्योंकि कई विमानन कंपनियों ने साप्ताहिक भुगतान प्रक्रिया में घन वापसी की सुविधा को हटा लिया है और कंपनियां एजेंटों से रिफंड के लिए अलग आवेदन करने के लिए कह रही हैं। बैठक में टीएएफआई के प्रतिनिधियों ने मांग की कि रिफंड प्रक्रिया को सात दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, जबकि हालिया रिफंड आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने पर दो महीने तक का समय लगता है। एजेंटों ने आयटा को यह भी कहा कि वह एजेंटों को दिवालिया होने से बचाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति का भी ख्याल करे।

टोटाल एसए का अदाणी ग्रीन संग संयुक्त उद्यम

फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी टोटाल एसए ने अदाणी समूह की अक्ष्य ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया है। इसके तहत संयुक्त उद्यम कंपनी में टोटाल 50 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 3,707 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

एजीईएल ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि इस संयुक्त उद्यम के पास 2 गीगावॉट की चालू सौर परियोजनाएं हैं और वह भारत के 11 शहरों में परिचालन कर रही है।

बयान में कहा गया है कि इस पोर्टफोलियो में प्रतिबंधित समूह 1 और 2 परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्होंने हाल में अमेरिकी बॉन्ड बाजार से 86.25 करोड़ डॉलर जुटाए थे। एजीईएल ने कहा है कि प्रतिबंधित समूह 2 भारत के अक्षय ऊर्जा कारोबार द्वारा लाया गया पहला निवेश ग्रेड रेटिंग (बीबीबी-/बीएए3/बीबीबी-) वाला निर्गम था। इसे वैश्विक पूंजी बाजार और अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में काफी सुर्खियां मिली थी।

कंपनी ने अपने बयान में कहा है, 'एजीईएल वर्ष 2025 तक 25 गीगावॉट क्षमता हासिल करने के लिए सही राह पर अग्रसर है। इसके साथ ही एजीईएल ने 2025 तक विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी बनने और 2030 तक विश्व की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है।' कंपनी ने कहा हैकि अदाणी समूह ने हाल में घोषणा की थी कि वह अपने बजटीय पूंजीगत खर्च में से 70 फीसदी से अधिक रकम का निवेश स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा कुशल प्रणालियों में करेगा। बीएस

उद्योग को रियायत की दरकार

केयर्न ऑयल ऐंड गैस का मानना है कि सरकार को पेट्रोलियम पर उपकर, रॉयल्टी और लाभ का भुगतान करने के बाद कोविड-19 की रोकथाम के लिए मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण उत्खनन कारोबार व्यावहारिक नहीं रह गया है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी **अजय दीक्षित** ने **शाइन जैकब** से बातचीत के मुख्य अंश:

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और लॉकडाउन का केयर्न जैसी कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

मैं कहना चाहूंगा कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) ब्लॉकों और मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सारणी पर कोरोना का जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। तेल कीमतों में गिरावट का कंपनी की लाभप्रदता पर भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है। बैंक भी इन कीमतों पर ऋण नहीं देना चाहते हैं।

सरकार को रॉयल्टी, उपकर और पेट्रोलियम मुनाफे पर राहत देने के बारे में विचार करना चाहिए। सरकार को निश्चित रूप से राहत देने पर विचार करना चाहिए क्योंकि उत्खनन कारोबार पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा है खासकर नेल्प-पूर्व उत्खनन ब्लॉकों में। नेल्प-पूर्व उत्खनन ब्लॉकों के लिए उत्पादकों की प्रमुख समस्या 20 फीसदी उपकर, 20 फीसदी रॉयल्टी और 50 फीसदी पेट्रोलियम मुनाफा देने की है। फिलहाल परिचालन खर्च बमुश्किल पूरा हो पाता है और ऐसे में इतनी बड़ी रकम का भुगतान करना कंपनी के लिए कठिन हो जाएगा। कंपनियां जबरदस्त चोट लगी है और चीजें सामान्य होने में कुछ तिमाही लगेंगे। तब तक सरकार को रियायत देने पर विचार करना चाहिए।

क्या आपने ओएलएपी की समय-सीमा में राहत के लिए फोर्स मेजर का इस्तेमाल किया है?

हमने ओएलएपी उत्खनन की समय-सीमा में विस्तार देने की मांग की है क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी सर्वेक्षण एवं गतिविधियां ठप हो गई हैं। ओएलएपी में चीजें काफी देरी से हो रही हैं। सामान्य तौर पर हम भूकंपीय कार्यों से शुरू करते हैं। इसके लिए अधिकतर उपकरणों की आपूर्ति चीन से होती है लेकिन दिसंबर से ही वहां से आपूर्ति बाधित है।

क्या उत्पादन में काफी गिरावट आई है?

हमारे उत्पादन में निश्चित तौर पर कमी आई है। इस साल के आरंभ में राजस्थान ब्लॉक से 1,80,000 बैरल (बीओईपीडी) का उत्पादन होता था जो अब घटकर 1,60,000 बैरल रह गया है। यदि कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो हमारा उत्पादन 2,10,000 बैरल तक पहुंच सकता था। हम कुछ परियोजनाओं के पूरे होने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन उसमें देरी हो रही है क्योंकि उसके लिए आवश्यक सामग्री चीन और इटली के बंदरगाहों पर फंसी पड़ी है जिसे जनवरी के अंत तक हमारे बंदरगाहों तक पहुंच जानी चाहिए थी।

सोने की कीमतों ने लगाई छलांग

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीतियों में नरमी की उम्मीदों के बीच सोना चमका

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 7 अप्रैल

विकसित देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक मंदी से बचाने के लिए मौद्रिक नीतियों को और आसान बनाने की उम्मीदों के बीच मंगलवार को सोने की कीमतों में 2.14 प्रतिशत की तेजी आई और यह अभी तक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मौद्रिक नीतियों को सरल करने से घटती ब्याज दरों तथा दूसरी परिसंपत्तियों के मुकाबले बेहतर रिटर्न की उम्मीद में सोने की कीमतों में तेजी आई।

लोकप्रिय जवेरी बाजार में स्टैंडर्ड सोने के दाम 940 रुपये बढ़कर मंगलवार को 44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि सोमवार को यह 43,760 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर दोपहर बाद के कारोबार में जून में डिलिवरी के लिए सोने का वायदा 2.82 प्रतिशत बढ़कर 44,955 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मई माह की डिलीवरी के लिए चांदी 5.41 प्रतिशत चढ़कर 43,455 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। लगभग सभी प्रमुख जिंसों के कारोबार में तेजी आने से मंगलवार दोपहर बाद के कारोबार में एमसीएक्स आईकॉमडेक्स 2.66 प्रतिशत बढ़कर 8,776.98 अंक पर पहुंच गया।

दुनिया भर में कोरोनोवायरस (कोविड-19) के मामलों की बढ़ती संख्या ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को संकट में डाल दिया है और विकसित तथा विकासशील देश लोगों को इस खतरे से बचाने के लिए मौद्रिक नीति को आसान बनाते हुए खरबों डॉलर की राशि अपनी अथव्यवस्थाओं में डाल रहे हैं।

नवंबर 2019 में वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने अब तक लगभग 160 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ईरान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने बताया कि वहां कुल 13 लाख संक्रमित व्यक्ति हैं और दुनियाभर में इससे 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है जिससे कारोबारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसलिए निवेशकों को अपनी कमाई सुरक्षित रखने के लिए सोना अच्छे विकल्प के तौर पर दिखाई दे रहा है।

कॉमनट्रेंड्ज के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित हुई है। निकट भविष्य में किसी तरह की राहत नहीं दिखने के चलते इस कठिन दौर में पेश किए उच्च प्रतिफल के साथ सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर सोना आसान विकल्प बन गया है जिसके चलते इसके दामों में भी तेजी देखने को मिल रही है।'

वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग 1,703 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही हैं, जो एक दशक का सबसे अधिक स्तर है। इससे पहले, साल 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के समय सोने की कीमतें 1,950 डॉलर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं।

भारत में, सोने ने एक महीने से भी कम समय में लगभग 20 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य सहित दूसरी सभी परिसंपत्ति वर्गों ने नकारात्मक रिटर्न दिया है।

आनंद राठी शेयर्स ऐंड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड के निदेशक नवीन माथुर ने कहा, 'डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती ने भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल को सीमित किया है।'

मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 49 पैसे मजबूत होकर 75.64 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

इस बीच, त्यागराजन का अनुमान है कि सोने की कीमतें 1,750 डॉलर प्रति औंस तथा आगे चलकर 1,780 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएंगी, जिससे भारत में सोने की कीमतें 47,000 - 47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाएंगी।

विश्लेषक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के लिए गुरुवार को होने वाली ओपेक बैठक पर भी दांव लगा रहे हैं। तेल उत्पादन में 1.5 मिलियन बैरल प्रति दिन कटौती प्रस्तावित है जिससे वैश्विक मांग में आई कमी को संतुलित किया जा सके। इसलिए, इस कटौती से कच्चे तेल की कीमतों या वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा।

वैश्विक कोशिशों के बीच सोने में आई तेजी

- मंगलवार को सोने की कीमतें 2.14 प्रतिशत बढ़ीं
- मुंबई के जवेरी बाजार में सोने के दाम चढ़कर 44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे
- मंगलवार को एमसीएक्स आईकॉमडेक्स 2.66 प्रतिशत बढ़कर 8,776.98 अंक पर पहुंचा

एमएससीआई में बदलाव से भारत में 7 अरब डॉलर आने की उम्मीद

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 7 अप्रैल

उभरते बाजारों में भारत का एमएससीआई भारांक 55 आधार अंक बढ़ेगा

विदेशी निवेशकों की तरफ से शेयरों में निवेश के लिए क्षेत्रवार सीमा को अधिसूचित करने में हुई देरी पर भारत कदम बढ़ा रहा है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों को उम्मीद है कि एमएससीआई उभरते बाजारों के इंडेक्स में भारत के भारांक को पुनर्संतुलित करेगा ताकि इस बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके, जिसमें डिपॉजिटरी रिसीट्स को विदेशी स्वामित्व की सीमा से हटाया जाएगा।

उन्हें उम्मीद है कि इसके परिणास्वरूप भारतीय इक्विटी में अनुमानित तौर पर 1.3 अरब डॉलर का पैसिव निवेश आएगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली को 5.7 अरब डॉलर ऐक्टिव निवेश आने का अनुमान है। इस तरह से कुल निवेश का अनुमान करीब 7 अरब डॉलर है। अक्टूबर में भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर भारतीय कंपनियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सांविधिक सीमा विदेशी निवेश की क्षेत्रीय सीमा (1 अप्रैल 2020 से प्रभावी) तक कर दी थी। हालांकि पिछले हफ्ते एमएससीआई ने बदलाव को टाल दिया था और कहा था कि वह इन बदलावों के लागू होने तक और नई क्षेत्रीय सीमा के व्यवस्थित प्रकाशन तक इंतजार करेगा और उसके बाद ही एमएससीआई इंडेक्स में किसी तरह का बदलाव करेगा।

मॉर्गन स्टैनली के भारतीय शोध प्रमुख और इक्विटी रणनीतिकार रिधम देसाई ने शीला राठी के साथ एक रिपोर्ट में कहा है, यह बदलाव वैश्विक बाजारों के मुकाबले कम सार्वजनिक शेयरों की उपलब्धता में सुधार की कोशिश है। अगले कुछ महीने में हमें उम्मीद है कि एमएससीआई इस बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए भारत के भारांक में बदलाव करेगा और इस आकलन से डिपॉजिटरी रिसीट्स को अलग रखेगा। हमारा अनुमान है कि उभरते बाजारों में भारत का एमएससीआई भारांक 55 आधार अंक बढ़ेगा और भारत का विदेशी इनक्लूजन फैक्टर 0.39 से 0.42 हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है, जब भी एमएससीआई बदलाव करेगा तब मौजूदा दौर में शामिल करीब एक तिहाई अपने शेयरों के भारांक में बढ़ोतरी देखेगा। एलऐंडटी, बजाज फाइनैंस, नेस्ले इंडिया और डिवीज लैब इस बदलाव से पांच अग्रणी लाभार्थी होंगे क्योंकि ये कंपनियां इंडेक्स में अपने भारांक में अधिकतम बढ़ोतरी देख सकती हैं। दूसरी ओर सापेक्ष आधार पर लार्जकैप शेयरों मसलन आरआईएल, एचडीएफसी और इन्फोसिस अपने भारांक में सबसे ज्यादा कमी का सामना कर सकती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, बायोकॉन और आईजीएल तीन अग्रणी शेयर हैं जिन्हें इस इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है।

रुपये में गिरावट से एमएनसी के लिए बेहतर हुई कर निपटान योजना

आयकर विभाग से एमएनसी की भारतीय सहायकों ने किया संपर्क

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 7 अप्रैल

रुपये में तेज गिरावट ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कर निपटान योजना 'विवाद से विश्वास' को बेहतर बना दिया है। आयकर विभाग से कई विदेशी फर्मों की सहायक कंपनियों ने यह जानने के लिए संपर्क किया है कि अगर वे यह योजना अपनाते हैं तो उन्हें कितना कर देना होगा। कर अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, खास तौर से स्थायी ठिकाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां या उनकी सहायक विनिमय दर का अंतर भुनाना चाहती हैं, जिससे मूल कंपनी को कुल कर में कम से कम 15-20 फीसदी का फायदा मिल सकता है, जो लंबे समय से कानूनी विवाद में अटका हुआ है।

समझा जाता है कि विदेशी फर्मों ने भारतीय सहायक को इस योजना में भागीदारी के लिए आगे बढ़ने और रुपये की कम कीमत का फायदा उठाने को कहा है, जिससे अंतत: उन्हें फायदा होगा। यह उन्हें विदेशी मुद्रा पर किसी तरह के नुकसान की भरपाई में भी मदद करेगा, जो आयात पर हो सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास है और देश में कोविड-19 के बढ़ते मामले और कमजोर देसी इक्विटी के बीच 76.01 पर कारोबार कर रहा है।

विशेषज्ञों ने कहा कि महामारी के खत्म होने तक रुपये पर दबाव बना रह सकता है।

एक अधिकारी ने कहा, कर भुगतान के दिन के विनिमय दर के आधार पर रुपये में यह भुगतान होता है। ऐसे में कंपनियों की तरफ से जो भी भुगतान होगा वह उस दिन के विनिमय दर पर निर्भर करेगा। इस संबंध में हाल में कुछ कंपनियों ने हमसे संपर्क किया है, जहां विदेशी सहायक कंपनियां लंबित कर मामले के निपटान के लिए यह योजना अपनाना चाहते हैं। अगर किसी भारतीय सहायक की 75 रुपये की विवादित कर की रकम पर अपील लंबित है तो डॉलर रुपये की विनिमय दर 75 रुपये के हिसाब से इस योजना में भारतीय सहायक के लिए भागीदारी की प्रभावी लागत एक डॉलर होगी और ऐसा करके वह ब्याज से मुक्त हो सकती है।

हालांकि अगर ऐसी भारतीय सहायक इस योजना का फायदा नहीं लेने का फैसला लेती है और भारतीय रुपया सुधरकर डॉलर के मुकाबले 67.50 पर आ जाता है तो जब इस अपील पर फैसला होगा तब कर की प्रभावी लागत उसके लिए 1.11 डॉलर होगी और इसमें जुर्माने का ब्याज शामिल होगा।

खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर संजय सांघवी ने कहा, विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायकों को रुपये की स्थिति पर विचार करना चाहिए। चूंकि ये सहायक विदेशी समूह की हैं, लिहाजा एमएनसी अपने फायदे के लिए रुपये की वैल्यू का इस्तेमाल कर सकती है। दिलचस्प रूप से भारतीय रुपये में तेज गिरावट के साथ इस योजना में भागीदारी के लिए प्रभावी लागत काफी कम हो गई है। सही कहा गया है कि एक व्यक्ति का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। ऐसे में भारतीय सहायकों को इसका आकलन करना चाहिए कि क्या भारतीय मुद्रा में गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है और उसके आधार पर वह विवाद से विश्वास योजना में भागीदारी की सोच सकती है।

सरकार की तरफ से इस योजना का विस्तार 30 जून तक किए जाने से कर विभाग से काफी पूछताछ हो रही है। इस तारीख तक कर विवाद के निपटान पर ब्याज नहीं लगेगा। मूल योजना के तहत अगर कोई करदाता 31 मार्च के बाद भुगतान करता तो उसे कुछ अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। यह भारत से बाहर स्थित विदेशी सहायकों के लिए भी प्रासंगिक है।

बीएस बातचीत

आकर्षक दायरे में है बाजार

निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड के सीआईओ (इक्विटी निवेश) **मनीष गुनवानी** ने **ऐश्ली कुटिन्हो** के साथ साक्षात्कार में कहा कि वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी वृद्धि और आय अनुमानों से संबंधित कई धारणाएं बदल जाएंगी। उन्होंने बताया कि कई शेयरों में संभावित मंदी का असर दिखा है और वे आकर्षक दायरे में आ गए हैं। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

इस साल बाजार के लिए आपका क्या नजरिया है? क्या कोविड-19 महामारी की वजह से बाजारों में गिरावट ज्यादा आई है?

आर्थिक दृष्टिकोण से, इस महामारी से अल्पावधि में गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि कई उद्योगों में कामकाज अचानक ठप हो गया है। माना जा रहा है कि वैश्विक और घरेलू, दोनों अर्थव्यवस्थाएं अगले 3 से 6 महीने में फिर से पटरी पर लौट सकती हैं। जहां तक बाजार की प्रतिक्रिया का सवाल है तो यह अल्पावधि के नजरिये से समझने योग्य है, क्योंकि जीडीपी वृद्धि और आय अनुमानों के संबंध में कई धारणाएं वित्त वर्ष 2021 के लिए बदल जाएंगी। दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य से, हमें विश्वास है कि बड़ी तादाद में शेयरों में संभावित मंदी का असर दिखा है और उन्होंने आकर्षक मूल्यांकन की पेशकश की है।

फंड प्रबंधक इस उथल-पुथल के दौर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप कैश कॉल पर जोर दे रहे हैं या किसी भी तरह से पूंजी पुन: आवंटित कर रहे हैं?

हम कैश कॉल नहीं बढ़ा रहे हैं और बाजार को तीन महीने पहले की तुलना में अब ज्यादा आकर्षक मान रहे हैं, क्योंकि मूल्यांकन काफी सस्ता है। कुछ खास मात्रा में पूंजी पुन: लगाने के संदर्भ में हम कुछ चक्रीय शेयरों की एवरेजिंग कर रहे हैं और उन क्षेत्रों को भी शामिल कर रहे हैं जिन्हें रुपये की गिरावट का लाभ मिले।

सरकार और आरबीआई द्वारा घोषित ताजा उपायों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

सरकार और आरबीआई द्वारा नीतिगत समर्थन से अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था को व्यापक तौर पर मदद मिलेगी। मौजूदा समय में सभी सेगमेंट के कॉरपोरेट सेक्टर को समर्थन की जरूरत है और सरकार तथा आरबीआई ने कुछ हद तक यह सहायता मुहैया कराई है।

वित्त वर्ष 2021 के लिए आय वृद्धि को लेकर आपका क्या नजरिया है? व्यवसायों और अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का कितना प्रभाव पड़ेगा?

वित्त वर्ष 2021 की आय का अनुमान लगाना कठिन होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधि ठप रहने की वजह से पहली तिमाही पर ज्यादा दबाव रहेगा। यह समझना उचित है कि वित्त वर्ष 2022 में कुछ वृद्धि दिखेगी। प्रत्येक उद्योग में सिर्फ प्रमुख दो-तीन कंपनियां ही अगली कुछ तिमाहियों में बाजार भागीदारी बढ़ा सकेंगी, क्योंकि छोटी कंपनियों की बैलेंस शीट पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है।

बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों पर आपकी क्या राय है?

उधारी एक जोखिम वाला व्यवसाय है और इस तरह के व्यवसाय पर ऐसी स्थिति में ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े झटकों में से एक से गुजर रही हो। अल्पावधि परिदृश्य चुनौतीपूर्ण है, पर बदलते समय के साथ अच्छी देनदारी फ्रैंचाइजी वाले बड़े बैंक विजेता बनकर उभर सकते हैं।

आप कौन से क्षेत्रों पर दांव लगा रहे हैं?

हम जिस थीम के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वह है चक्रीयता वाले क्षेत्रों में मजबूत बैलेंस शीट, जिससे कि अर्थव्यवस्था के सुधरने पर उन्हें वृहद अनुकूल परिवेश और बाजार भागीदारी दोनों के लिहाज से फायदा हो सके। हम वाहन, रियल एस्टेट, विमानन, बीमा और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में ऐसे अवसर देख रहे हैं।

एसआईपी प्रवाह और एकमुश्त निवेश के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है?

म्युचुअल फंड उद्योग अभी भी लगातार पूंजी प्रवाह आकर्षित कर रहा है। हालांकि अल्पावधि प्रतिफल कमजोर हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि बाजार एकमुश्त निवेश बढ़ाने के लिहाज से निवेशकों के लिए आकर्षक स्थिति में बना हुआ है। हमारा मानना है कि इस तरह की बड़ी गिरावट का इस्तेमाल इक्विटी में निवेश बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। वर्ष 2009, 2013 और 2015 में इक्विटी आवंटन वृद्धि ने निवेशकों को काफी हद तक लाभान्वित किया।

बीपीएल मेडिकल टेक ने बनाया वेंटिलेटर का प्रारूप

विभु रंजन मिश्रा
बेंगलूरु, 7 अप्रैल

एनस्थीसिया मशीन, एक्स-रे उपकरण, वेपोराइजर और ऑक्सिजन जेनरेटर बनाने वाली बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजिज वेंटिलेटर की डिजाइनिंग व विनिर्माण की प्रक्रिया में है ताकि देश की तत्काल जरूरतों को पूरा कर सके। कोविड-19 के मरीजों के इलाजा में वेंटिलेटर की उपलब्धता काफी अहम हो गई है।

गोल्डमैन सैक्स समर्थित चिकित्सा उपकरण विनिर्माता बेंगलूरु की आरऐंडडी टीम और केरल के पलक्कड़ स्थित विनिर्माण संयंत्र की टीम के जरिए वेंटिलेटर का प्रारूप बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है, जो जल्द तैयार होने की उम्मीद है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक सुनील खुराना ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, विशेषज्ञों के अहम मूल्यांकन और जांच के बाद यह डिजायन अप्रैल के मध्य तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा।

- दो हफ्ते में उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद है
- गोल्डमैन सैक्स समर्थित कंपनी अभी वेपोराइजर्स, एनस्थीशिया मशीन और ऑक्सीजन जेनरेटर बनाती है

खुराना ने कहा, यह वेंटिलेटर शायद बहुत महंगा नहीं होगा क्योंकि हमारी योजना ज्यादा न्यूमैटिक्स सिस्टम लाने की है, लेकिन यह अच्छी गुणवत्ता वाला आपातकालीन वेंटिलेटर होगा। हम इस पर जूनून के साथ काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यह न सिर्फ भरोसेमंद होगा बल्कि उसे सही कीमत पर भी पेश किया जा सकेगा।

जटिलताओं के आधार पर वेंटिलेटर की कीमतें 6-7 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रुपये तक होती है, जो मुख्य रूप से महंगे वेंटिलेटर हैं। खुराना के मुताबिक, बीपीएल मेडिकल टेक जो वेंटिलेटर बना रही है वह मध्यम श्रेणी की होगी, जो वैसे कोविड-19 के मरीजों के लिए पर्याप्त होगा, जो मुख्य रूप से बड़ी उम्र के लोग हैं। हम जो बना रहे हैं उसकी पेशकश नवजात के इलाज में नहीं की जाएगी।

कोविड-19 के मरीजों के इलाज में वेंटिलेटर की उपलब्धता अहम हो गई है। कई अनुमानों के मुताबिक, भारत की करीब 1.2 अरब आबादी के लिए महज 50,000 वेंटिलेटर ही उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर का आयात वैश्विक कंपनियों से किया गया है। उदाहरण के लिए बीपीएल हेल्थ टेक भारत में जर्मनी की वेंटिलेटर विनिर्माता कंपनी लोर्वेंस्टिन की रीसेलर भी है।

खुराना ने कहा, बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजिज के पास तकनीक की काफी समझ है, लेकिन हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी पेनियन से सरकार ने संपर्क किया है और स्थानीय बाजार के लिए वेंटिलेटर बनाने को कहा है। ब्रिटिश सरकार ने कंसोर्टियम के गठन के लिए विभिन्न कलपुर्जा विनिर्माताओं को शामिल किया है, वहीं अंतिम उत्पाद पेनियन की फैक्टरी से निकलेगी। उन्होंने कहा, हम ब्रिटेन की फैक्टरी में इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं और अगले हफ्ते से हम काफी ज्यदा मशीनों का निर्यात शुरू करेंगे। हालांकि अभी जितना काम है उसे देखते हुए बीपीएल मेडिकल टेक कम से कम अगले दो-तीन महीने तक भारत में तकनीक और आपूर्ति आधार लाने में सक्षम नहीं होगी जब तक कि वह ब्रिटिश सरकार की जरूरतें पूरी नहीं कर देती। साल 2015 में बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजिज ने पेनियन का अधिग्रहण किया था और इस तरह से विदेश में यह कंपनी का पहला अधिग्रहण था। तब से कंपनी ने 75 साल पुराने इस ब्रांड में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है।

खुराना ने कहा, कंपनी का पलक्कड़ विनिर्माण संयंत्र वेंटिलेटर के लि पूरी तरह से सुसज्जित है। हम उन उत्पादों पर पूरी टीम लगा देंगे, जो सिर्फ कोविड के लिए होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कलपुर्जे की खरीदारी में कोई समस्या नहीं होगी। बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजिज में नांबियार फैमिली की करीब 35 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो वह वित्त वर्ष 2021 में 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल कर लेगी।

संक्षेप में

निर्यात वस्तुओं के स्रोत का प्रमाण पत्र ऑनलाइन

वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापार समझौते वाले देशों के साथ वस्तुओं के निर्यात के लिए जरूरी दस्तावेज जारी करने को लेकर ऑनलाइन मंच तैयार किया है। इस पहल का मकसद कोरोना वायरस संकट के दौरान वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाना है। निर्यातक को आयातक देश को वस्तु के स्रोत या उत्पत्ति के देश के बारे में प्रमाणपत्र देना होता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मंगलवार को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया। *भाषा*

जनवरी-मार्च में आवास बिक्री 29 प्रतिशत गिरी

आवासों की बिक्री जनवरी-मार्च अवधि में 29 प्रतिशत घटी है। सात प्रमुख शहरों में इस दौरान मात्र 27,451 आवास बिके और 3.65 लाख करोड़ रुपये के मकान बिक्री के लिए तैयार खड़े थे। संपत्ति सलाहकार कंपनी जेएलएल ने कहा कि कोरोनावायरस संकट को देखते हुए अभी ज्यादा खरीदार नहीं हैं। इस दौरान आवास बिक्री 29 प्रतिशत घटकर 27,451 इकाई रह गई है। *भाषा*

राज्यों को बकाया जीएसटी मुआवजा देगा केंद्र

अरूप रायचौधरी और दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 7 अप्रैल

वित्त मंत्रालय शीघ्र ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा बकाये में से राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है। यह भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर में से नहीं, बल्कि भारत की संचित निधि से किया जाएगा और यह राशि कुछ दिनों पहले ही केंद्र की ओर से राज्यों को अंतरण और आपदा कोष के तौर पर बांटे गए 17,287 करोड़ रुपये के बाद दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय एक और प्रोत्साहन पैकेज पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा शीघ्र ही की जा सकती है। पैकेज की रकम को लेकर अभी कोई निश्चित आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह फिर से शहरी और ग्रामीण गरीब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कोविड-19 महामारी व उसके कारण की गई बंदी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।

प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रहे अधिकारी कहते हैं कि बहुत से ऐसे लगातार बदलते कारक हैं जिन पर अभी भी विचार हो रहा है, जबकि पैकेज को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन कारकों में कोविड-19 के सक्रिय मामले, महामारी के हॉटस्पॉट और 14 अप्रैल के बाद देशव्यापी बंदी की स्थिति आदि हैं।

सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'राज्यों के जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाये में से 20,000 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत कर दिया गया है।' एक अन्य अधिकरी ने कहा, 'हम राज्यों को केवल क्षतिपूर्ति उपकर फंड से ही क्षतिपूर्ति का वितरण कर सकते हैं। चूंकि वह उपलब्ध नहीं है, इसे संचित निधि से जारी करने की मंजूरी दी गई है।'

केंद्र सरकार के अधिकारी कहते हैं कि सभी को पता है कि फिलहाल स्रोत का संकट है लेकिन राज्यों को ज्यादा धन दिया जाएगा। राज्यों को 2020-21 में उनकी कुल उधारी का 50 फीसदी अप्रैल में ही लेने की अनुमति भी दी गई है।

राज्य कर रहे थे लंबे समय से मांग

वर्ष	उपकर संग्रह	राज्यों को जारी	बचा उपकर
2017-18	62,596	41,146	21,600
2018-19	95,081	69,275	25,500
2019-20*	95,768	1,20,498	-24,730

* अप्रैल से मार्च तक का संग्रह और अप्रैल से अक्टूबर तक का राज्यों को भुगतान

- वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय एक और प्रोत्साहन पैकेज पर कर रहे हैं काम
- शहरी व ग्रामीण गरीब, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों पर केंद्रित होगा पैकेज

महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से 25,000 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज की मांग की है और विभिन्न मदों में 31 मार्च तक के 16,654 करोड़ रुपये के लंबित बकायों का भुगतान करने के लिए कहा है ताकि कोरोनावायरस महामारी से उपजे वित्तीय संकट का मुकाबला किया जा सके।

तमिलनाडु ने 4,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता और कई दूसरे वित्तीय समर्थन देने की मांग की है। पश्चिम बंगाल ने भी 25,000 करोड़ रुपये के पैकेज और 36,000 करोड़ रुपये के बकाये की मंजूरी देने की मांग की है। इसके अलावा सभी राज्यों ने उनकी उधारी सीमा में राहत देने की मांग की है।

पूरे साल के महज 95,000 करोड़ रुपये के उपकर संग्रह के मुकाबले कुल वितरण 1.2 लाख करोड़ रुपये का रहा। सच्चाई यह है कि यह 98,327 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 3,000 करोड़ रुपये कम है।

क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान हर दो महीने पर किया जाता है जो पांच महीने से लंबित है। अभी भी 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति लंबित होने के कारण कुछ राज्य केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय में घसीटने की योजना बना रहे हैं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजक ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'भारत के इतिहास में कभी भी केंद्र का राज्यों के प्रति इतना कठोर बर्ताव नहीं रहा। ऐसे में राज्यों के पास सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।'

केंद्र सरकार अक्टूबर और नवंबर के लिए बकाये का 65 फीसदी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार का मानना था कि वह क्षतिपूर्ति का भुगतान केवल विलासिता और वाहन, तंबाकू तथा वातित पेयों से मिले उपकर से करेगी।अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति का बकाया 2016-17 और 2018-19 में संग्रह से दो किस्तों में की जाएगी।

ई-कॉमर्स फर्में चाहती हैं 6 महीने का कर्फ्यू पास

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 7 अप्रैल

एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, ग्रोफर्स जैसी ई कॉमर्स कंपनियों और विक्रेताओं ने 4 से 6 महीने के लिए कर्फ्यू पास जारी करने के लिए सरकार से मदद मांगी है। सूत्रों का कहना है कि आईटी उत्पादों सहित जरूरी सामान की सूची को भी मंजूरी दिए जाने के लिए सरकार से बात हो रही है।

ई-कॉमर्स फर्मों और विक्रेताओं का कहना है कि 4-6 महीने की अवधि मिलने पर वे स्टॉक तैयार रख सकेंगे, जिनका मानना है कि अभी जारी कर्फ्यू पास देशबंदी हटते ही 14 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। फर्मों ने डिजिटल कर्फ्यू पास जारी किए जाने की मांग की है। उनका मानना है कि अगर सरकार 14 अप्रैल के बाद देशबंदी जारी रखती है तो देश के विभिन्न शहरों व जिलों के स्थानीय प्राधिकारियों से कर्फ्यू पास जारी कराना उनके लिए बहुत श्रमसाध्य होगा।

एक ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'अभी दिए गए सभी पास और मंजूरियां 14 अप्रैल तक के लिए हैं। ऐसे में कल्पना करें कि अगर देशबंदी 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ती है तो आपको फिर से पास के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी।' उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि यह देशबंदी कब तक चलने वाली है।

इस समय डिलिवरी देने वाले ज्यादातर अपने गांव लौट गए हैं, ऐसे में कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही का पास हासिल करने के लिए जूझ रही हैं।

एक जिले से दूसरे जिले जाने के बजाय ऑनलाइन खुदरा कारोबारियों ने सरकार से यह भी कहा है कि हर राज्य को पास जारी कराने में सक्षम बनाया जाए। खुदरा से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'अगर हमारे डिलिवरी सहायक को दक्षिण दिल्ली का पास मिलता है तो वह उत्तर दिल्ली में डिलिवरी नहीं दे सकता है।' उन्होंने कहा कि अगर गोदाम दिल्ली के उत्तरी हिस्से में है तो हो सकता है कि डिलिवरी सहायक दक्षिण दिल्ली में रहता हो और उसे घर से गोदाम तक आना जाना होगा और माल उठाने के बाद डिलिवरी करना होगा। इस तरह से तमाम डिलिवरी करने वाले कर्मियों को पुलिस रोक रही है।

संगठित खुदरा में 25 प्रतिशत बंदी की ओर

सुरजीत दासगुप्ता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल

खुदरा क्षेत्र से चिंताजनक खबर है। रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आरएआई) के अनुमान के मुताबिक करीब 25 प्रतिशत आधुनिक खुदरा कारोबारियों को नकदी की सख्त जरूरत है, अन्यथा उन्हें कारोबार समेटना पड़ेगा।

आरएआई के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा, 'अगर सरकार बचाव के लिए आगे नहीं आती तो कठिन स्थिति है। गैर खाद्य खुदरा कारोबारियों के पास देशबंदी के दौरान इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वह पहले से तय लागत जारी रख सकें।'

एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों का कहना है कि उन्हें कारोबार बचाए रखने के लिए 20 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाना पड़ सकता है, वहीं छोटे खुदरा कारोबारियों का कहना है कि उन्हें कोविड के बाद 30 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाना पड़ सकता है।

वहीं खुदरा क्षेत्र के रिलायंस रिटेल जैसे बड़े दिग्गज शॉपिंग मॉल और रियल एस्टेट मालिकों को फोर्स मेजर का नोटिस भेज रहे थे, वे अब उनके साथ चर्चा कर वित्तीय बोझ साझा करने की योजना बना रहे हैं। रिलायंस रिटेल ने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है।

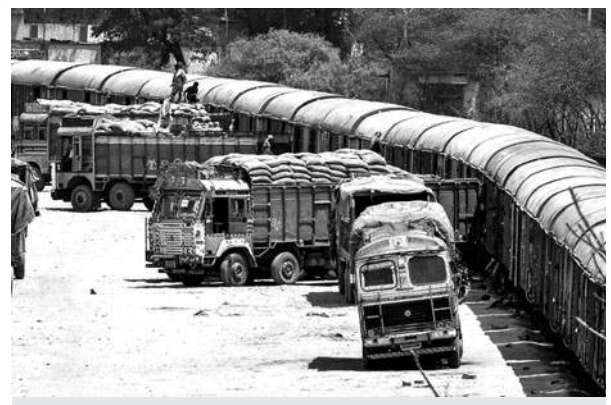

इस समय देशबंदी के कारण आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी खुदरा कारोबार बंद है, जिसकी मार कारोबारियों पर पड़ रही है। मंगलवार को रांची में नामकोम रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से खाद्यान्न उतारते मजदूर *फोटो-पीटीआई*

क्या सोचते हैं खुदरा कारोबारी

- 70 प्रतिशत लोग 6 महीने तक कोई रिकवरी नहीं देख रहे हैं, जिसमें साल भर से ज्यादा भी लग सकता है
- 20 प्रतिशत खुदरा क्षेत्र के कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, इस क्षेत्र के कुल कर्मचारी 4 से 5 करोड़
- खुदरा क्षेत्र की परिचालन लागत में 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा किराये का, चाहते हैं किराये से छूट

आरएआई ने संगठित खुदरा क्षेत्र के 768 सदस्यों (इनमें छोटी, मझोली और बड़ी श्रृंखलाएं शामिल हैं) के बीच अध्ययन कराया। इनमें से 51 प्रतिशत ने कहा कि अब 6 से 12 महीने में ही रिकवरी हो सकती है। वहीं 24 प्रतिशत ने ज्यादा आशावाद दिखाते हुए यह समयसीमा 3 से 6 महीने रखी है।

साथ ही 80 प्रतिशत को अगस्त तक किसी मुनाफे की उम्मीद नहीं है और अगले 6 महीने में गैर खाद्य खुदरा कारोबारी कहते हैं कि पिछले साल की समान अवधि में आए राजस्व की तुलना में सिर्फ 40 प्रतिशत राजस्व आने की उम्मीद है। इस सर्वे में शामिल होने वाले करीब 18 प्रतिशत खाद्य क्षेत्र के खुदरा कारोबारी हैं, जिन्होंने देशबंदी के दौरान कारोबार बंद नहीं किया है। शेष गैर खुदरा क्षेत्र के हैं, जिन्हें कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

इस बात पर सहमति है कि मॉल मालिक देशबंदी के दौरान किराये में माफी को इच्छुक हैं। बहरहाल ज्यादातर खुदरा कारोबारियों का कहना है कि उनकी समस्या नकदी प्रवाह न होने को लेकर है, जो कम से कम 2-3 तिमाही नहीं आने वाली है। ऐसे में वे पर्याप्त कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।

राजगोपालन का कहना है, 'मांग और आपूर्ति में अंतर है। उसी के अनुपात में किराया कम होना चाहिए। कुल मिलाकर कुल लागत में किराया ही करीब 35-40 प्रतिशत होता है। उसके बाद 30 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन पर और शेष खर्च माल रखने पर आता है।'

खुदरा बिक्री घटने से मॉल मालिकों पर बढ़ा दबाव

राघवेंद्र कामत और विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 7 अप्रैल

मॉल डेवलपर्स और खुदरा कारोबारियों के बीच किराया माफी के विवादास्पद मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। उनके बीच यह मतभेद ऐसे समय पर उभरे हैं जब ग्रॉसरी को छोड़ कर खुदरा उद्योग के पास 24 मार्च से घोषित बंदी के कारण किराया रोकने का कारण है।

डीएलएफ और फीनिक्स मिल्स जैसे डेवलपर कहते हैं कि खुदरा कारोबारियों ने पूर्ण बंदी होने के कारण 'अप्रत्याशित घटना' का उपनियम लगाने का संकेत दिया है जो किसी भी सूरत में बंदी की अवधि पर लागू नहीं होता है।

मुंबई, पुणे, बेंगलूरु और दूसरे शहरों में मॉल का परिचालन करने वाली फीनिक्स मिल्स के प्रबंध निदेशक शिशिर श्रीवास्तव कहते हैं, 'हमें खुदरा कारोबारियों के साथ किराये के मुद्दे पर मिलकर काम करना होगा। मॉल खुलने की गुंजाइश बनने के बाद ही हम निर्णय कर सकते हैं।'

मोदी सरकार की ओर से घोषित 21 दिनों की देशबंदी 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। लेकिन देश में कोरोनावायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अपने स्तर पर बंदी की अवधि को बढ़ा सकती हैं।

श्रीवास्तव कहते हैं कि सरकार के निर्देश के कारण जब मॉलों, मल्टीप्लेक्सों और खुदरा प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद रखा गया है तो 'अप्रत्याशित घटना' का उपनियम लगाने को कोई अर्थ नहीं है। वह कहते हैं कि कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा जिसका खुदरा कारोबारी बाजार कमजोर रहने का हवाला देकर विरोध कर रहे हैं।

वी-मार्ट रिटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ साथ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) के सदस्य ने कहा कि मॉल मालिक पार्टनर हैं और ये खुदरा कारोबारी समस्या के उचित समाधान पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह प्रयास मॉल मालिकों के साथ हमारे संबंध को खराब करने वाला है। वे महत्त्वपूर्ण पार्टनर हैं। लेकिन ज्यादातर खुदरा कारोबारी मॉल मालिकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में नतीजे बातचीत के आधार पर अलग अलग होंगे।' किराया माफी के मुद्दे पर एक स्पष्ट कार्य योजना के अभाव में डेवलपरों ने कहा कि वे सामूहिक स्थल के रखरखाव पर लगने वाले शुल्क को घटाने और इसे खुदरा कारोबारियों के कंधों पर डालने पर काम कर रहे हैं।

इसके उलट जिन डेवलपरों से बिजनेस स्टैंडर्ड ने बातचीत की है, उनका कहना है कि उन्होंने अब तक अपने ग्राहकों के लिए किराये की रसीद नहीं निकाली है जिसका मतलब है कि परिस्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से उन पर ही नहीं छोड़ दिया गया है।

डीएलएफ शॉपिंग मॉल्स की कार्यकारी निदेशक पुष्पा बेक्टर ने कहा, 'ऐसे समय में हमें धैर्य से काम लेने की जरूरत है और नए सिरे से सामान्य होने के लिए कारोबारी रणनीति बनाई जानी चाहिए।' आरएआई के मुख्य कार्याधिकारी कुमार राजगोपालन ने कहा कि खुदरा कंपनियों के ज्यादातर प्रमुख उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी से उपजे संकट और उसके बाद हुई बंदी अप्रैल-जून तिमाही से आगे जा सकती है।

उन्होंने कहा, 'इस संकट से उबरने में करीब नौ महीने का समय लग सकता है और खुदरा कारोबारी सरकार, बैंकों और सहायोगी साझेदारों की सहायता से इस अवधि से पार पा लेंगे। आगे का रास्ता साझेदारी से निकलेगा।'

आरएआई ने सरकार से तुरंत राहत कदम उठाने के लिए कहा है ताकि करीब 60 लाख लोगों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र को पर्याप्त पूंजी मिल सके। इसके तहत खुदरा कारोबारियों को ऋण भुगतान पर दी गई मोहलत को बढ़ाकर 270 दिन किए जाने, नकदी संकट से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मुहैया कराने और मजदूरी तथा वेतनों के भुगतान के लिए आसान क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराने की जरूरत है। भय इस बात है कि यदि तेजी से राहत उपाय नहीं किए गए तो बाजार में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले छोटे और मध्यम खुदरा कारोबारी अगले कुछ महीनों में इससे बाहर हो जाएंगे।

बियोंड स्क्वायरफीट एडवाइजरी के संस्थापक सुशील एस डुंगरवाल ने कहा, 'ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे और मध्यम खुदरा ब्रांडों के पास प्रमुख जगहों पर भूस्वामियों के साथ अप्रत्याशित घटना का उपनियम नहीं है।'

दवा निर्यात में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का हिस्सा मामूली

सोहिनी दास
मुंबई, 7 अप्रैल

भारत हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 19 में देश से 5.1 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। देश के कुल 19 अरब डॉलर के दवा निर्यात में इसका हिस्सा बहुत मामूली है।

बहरहाल वित्त वर्ष 2020 में फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक दवा का निर्यात 3.6 करोड़ डॉलर कम रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप एचसीक्यू की हिमायत कर रहे हैं, ऐसे में अचानक इस दवा की वैश्विक मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। ब्राजील और भारत के सार्क पड़ोसी देशों ने भारत से दवा की मांग की है।

केंद्र ने खुद ही आईपीसीए लैबोरेटरीज और कैडिला हेल्थकेयर से 10 करोड़ टैबलेट की जरूरत बताई है। विनिर्माताओं का कहना है कि भारत के बाजारों में पर्याप्त स्टॉक है और अतिरिक्त दवाओं का निर्यात किया जा सकता है। वे सरकार को इस महीने में इसकी आपूर्ति की कवायद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चीन एचसीक्यू नहीं बनाता और भारत ही विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

एचसीक्यू और क्लोरोक्वीन फॉस्फेट एक ही वर्ग की दवाएं हैं।

क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया के मरीजों के उपचार के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ एचसीक्यू का इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे आर्थराइटिस, लूपस और मधुमेह की तीसरी श्रेणी के उपचार के लिए होता है। कुछ स्वास्थ्य शोधार्थी एचसीक्यू का सामान्य एंटीबायोटिक्स एजीथ्रोमाइसिन के साथ इस्तेमाल कर कोविड-19 का उपचार करने की कवायद कर रहे हैं।

सरकार ने एक परामर्श में एचसीक्यू का इस्तेमाल स्वास्थ्य कर्मियों और ज्यादा जोखिम वाले लोगों को करने की सलाह दी है, जिससे उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके।

इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों के लिए भी हो रहा है। विशेषज्ञों ने इसके व्यापक इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है, जब तक कि क्लीनिकल ट्रायल के बाद यह दवा संदेह से परे नहीं हो जाती है।

अमेरिकी एफडीए ने 19 मार्च की विज्ञप्ति में कहा है कि वह अन्य सरकारी एजेंसियों व अध्ययन केंद्रों के साथ मिलकर क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल की जांच कर रहा है कि इसका कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं।

भारत में एचसीक्यू की बिक्री तेज हो गई है। मार्केट रिसर्च फर्म एआईओसीडी एडब्ल्यूएसीएस के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में एचसीक्यू की बिक्री में 19 प्रतिशत की तेजी आई है। इसकी वजह यह है कि अचानक चर्चा में आने की वजह से तमाम भारतीय इसे खरीदकर रख रहे हैं, जिसकी कीमत बमुश्किल 3 रुपये प्रति टैबलेट है।

बहरहाल अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पर्याप्त मात्रा में है?

प्रमुख विनिर्माताओं ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि स्थानीय आपूर्ति को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। भारत जरूरत पड़ने पर हर महीने 100 टन दवा बना सकता है और इसकी क्षमता आसानी से बढ़ाई जा सकती है।

इस दवा की प्रमुख उत्पादक आईपीसीए है और यूएस एफडीए ने हाल में उसके संयंत्र से आयात अलर्ट हटा दिया है, जिससे वह अमेरिका को निर्यात कर सकती है। कैडिला पहले से ही अमेरिका को निर्यात कर रही है, हालांकि मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है।

भारत में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक विनिर्माता ने साफ किया, 'एक मरीज को 14 टैबलेट देने की जरूरत होती है। 10 करोड़ टैबलेट से भारत 7 करोड़ लोगों का इलाज कर सकता है। अगर मामले बढ़कर एक महीने में 1,00,000 तक पहुंच जाते हैं और हर मरीज को 3 स्वास्थ्यकर्मी की जरूरत हो, तब भी देश में पर्याप्त स्टॉक है।'

भारत में पर्याप्त दवा

- कुछ स्वास्थ्य शोधार्थी कोविड-19 के उपचार में एचसीक्यू का सामान्य एंटीबायोटिक्स एजीथ्रोमाइसिन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं
- क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया के मरीजों के उपचार के लिए जबकि एचसीक्यू का इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में
- सरकार ने दी स्वास्थ्य कर्मियों व ज्यादा जोखिम वालों को संक्रमण से बचाने हेतु एचसीक्यू के इस्तेमाल की सलाह
- विशेषज्ञों ने कोविड-19 पर पर्याप्त परीक्षण के बगैर व्यापक इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी

कोविड-19 के इलाज मे क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को लेकर अमेरिकी एफडीए अन्य सरकारी एजेंसियों व अध्ययन केंद्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है

बीएस सूडोकू 3709

परिणाम संख्या 3608

6					4			
		9						
			5	9	1			2
9	7		8	5				
2		5					9	
				6		5	2	
	3		1					
	5				9	6	1	
4			7	8	6		3	

1	8	2	7	6	3	4	9	5
7	4	9	5	1	8	6	2	3
5	6	3	2	4	9	7	1	8
9	2	4	6	7	5	8	3	1
3	5	6	8	9	1	2	7	4
8	7	1	4	3	2	5	6	9
2	1	8	9	5	7	3	4	6
4	3	5	1	2	6	9	8	7
6	9	7	3	8	4	1	5	2

कैसे खेलें? बहुत मुश्किल

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

केंद्र के निर्देश के बावजूद बागान खोलने से इनकार

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 7 अप्रैल

कोविड-19 के प्रकोप के कारण पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में स्थिति अभी भी गंभीर होने कारण राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चाय बागानों को कारोबार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार का यह आदेश केंद्र की ओर से चाय उगाने वाली कंपनियों को देश भर में 50 फीसदी कार्यबल के साथ चाय उगाने का गतिविधि शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद आया है।

बनर्जी ने राज्य सरकार के इस आदेश का कारण बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा रणनीतिक स्थान है जहां पर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह इलाका पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम का एकमात्र प्रवेश द्वार भी है।

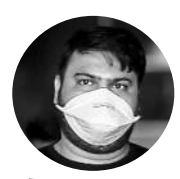

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस

बनर्जी ने कहा, 'हमें इसे कुछ और समय तक ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है और बागानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलिम्पोंग में स्थिति ठीक नहीं है और चाय बागान में काम करने वाले कामगारों के संक्रमित होने के जोखिम से बचना बेहतर निर्णय है।'

बहुत से चाय बागान कलिम्पोंग के करीब हैं। हालांकि ज्यादातर वे वर्ष भर स्वयं से ही पृथक्करण का पालन करते हैं। कलिम्पोंग में 2 अप्रैल को जान गंवाने वाली महिला के परिवार के छह सदस्यों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है।

दार्जिलिंग और दोआर में एस्टेट वाले उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, 'राज्य प्रशासन पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में सक्रियता से स्थिति पर नजर रख रहा है और संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया होगा।' हालांकि चाय कंपनियों को लगता है कि उन्हें अपने घाटे की भरपाई की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।

जय श्री टी ऐंड इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी डीपी माहेश्वरी ने कहा, 'हमें उम्मीद थी कि इस महीने थोड़ी भरपाई हो जाएगी। लेकिन अब यह उत्पादन पूरी तरह से बंद रहने का परिदृश्य होगा, जिससे भारी घाटा होगा।'

गुडरिक समूह के प्रबंध निदेशक अतुल अस्थाना ने कहा कि दार्जिलिंग में पहले से तैयार हो चुकी 8 लाख किलोग्राम की समूची फसल बरबाद हो चुकी है और दोआर की फसल को भी धक्का लगेगा। अप्रैल में हुए उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी करीब 28 फीसदी है जो करीब 8.5 करोड़ किलोग्राम बैठती है। असम की हिस्सेदारी 54 फीसदी है और बाकी हिस्सा दक्षिण भारत का है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 41

मददगार हो सरकार

सरकार ने सांसदों की वेतन कटौती का जो निर्णय लिया है वह इस मायने में बेहतर है कि सरकार कोविड-19 संकट के आकार को पहचान रही है। बहरहाल, यह कदम निजी क्षेत्र से सरकार की अपेक्षाओं के एकदम विरोधाभासी है। सरकार के लिए काम करने वाले श्रम आयुक्तों के कारण निजी कंपनियां श्रमिकों की तादाद कम नहीं कर पा रही हैं या वे कर्मचारियों को बिना भुगतान की छुट्टी पर भेजकर अपने खर्च कम नहीं कर पा रही हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय श्रम आयुक्त ने स्पाइसजेट से कहा है कि वह एक रिपोर्ट पेश करे कि उसने सरकार के मशविरों पर क्या कदम उठाया है। गौरतलब है कि कंपनी ने कुछ दिन पहले वेतन कटौती की घोषणा की थी। निजी क्षेत्र में नौकरियां और वेतन भत्ते बचाना अहम लक्ष्य है लेकिन सरकार को कारोबारों को चालू भी रखना है। श्रम बाजार की शर्तें लचीली रखने का लक्ष्य यही है कि वेतन-भत्तों और लागत को यथासंभव लचीला बनाया जा सके। यह बात अलग है कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में भी इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जब कारोबार गिरावट पर होते हैं तो ऊंची स्थायी लागत कंपनी की नकदी पर जोरदार चपत लगाती है। गौरतलब है कि वेतन इसका अहम हिस्सा होते हैं।

सरकार शायद यह नहीं समझ रही है कि यदि वेतन कटौती, जबरन छुट्टी जैसे उपाय नहीं अपनाने दिए गए तो कंपनियां पूरी तरह बंद भी हो सकती हैं। यह किसी के हित में नहीं होगा। विमानन उद्योग जैसे कई कारोबारों को सरकार ने ही बंद करने का आदेश दिया है। उनका राजस्व तो सरकार के आदेश की वजह से शून्य हुआ है। हालांकि सरकार ने ऐसा वायरस को थामने के लिए किया है लेकिन कई कंपनियां शायद ऐसी स्थिति में नहीं होंगी कि वे लंबे समय तक बिना राजस्व के नकदी बरकरार रख सकें। हकीकत में विमानन कंपनियों और होटल जैसे कारोबारों के लिए शायद लॉकडाउन के चरणबद्ध रूप से समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक हालात सामान्य न हो सकें। ऐसे में वेतन कैसे देंगे? ट्रकों की बिक्री 80-90 फीसदी तक गिर गई है। विनिर्माण का काम लगभग ठप है। जाहिर है तयशुदा लागत इनके कारोबार को ठप कर देगी। ये ऐसे कारोबार हैं जिन्हें परिचालन में काफी लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन्हें सरकार के समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। यदि ऐसा न हो तो बड़ी तादाद में कंपनियां दिवालिया होंगी और इससे काफी लोग बेरोजगार तो होंगे ही सुधार प्रक्रिया भी धीमी पड़ेगी। भारत इस अप्रत्याशित झटके से कितनी जल्दी निपटता है यह सरकार की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है।

यदि सरकार की प्राथमिकता सारे रोजगारों और श्रमिकों का संरक्षण करना है और वह नियोक्ताओं को अवसर नहीं देती है तो उसे वेतन भत्तों के एक हिस्से का बोझ तब तक उठाना चाहिए जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। ब्रिटेन में ऐसी घोषणा की जा चुकी है। ब्रिटिश सरकार रोजगार गंवाने वाले अधिकांश कर्मचारियों के वेतन भत्तों की भरपाई कर रही है। सरकार ने आबादी के संवेदनशील तबके के लिए पैकेज की घोषणा भी की है। परंतु कोविड-19 के आर्थिक असर से निपटने की व्यापक नीति अभी भी नदारद है। नीति निर्माताओं को जल्दी ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का खाका तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए कुछ कारोबारों की हालत सुधरने में अधिक वक्त लगेगा। सरकार अगर यह सुनिश्चित करे तो बेहतर होगा कि उनके सामने नकदी प्रवाह और नकदी का संकट नहीं आएगा। निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वेतन देते रहने का आदेश देने भर से काम नहीं चलेगा।

अजय मोहंती

भारतीय इसी अव्यवस्था के हकदार हैं?

कोरोनावायरस के चलते पैदा हुआ बड़ा संकट भारतीय आर्थिक प्रणाली की कई बड़ी खामियों को उजागर करता है। मौजूदा आर्थिक परिदृश्य का जायजा ले रहे हैं जैमिनी भगवती

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका, यूरोप और चीन में कोरोनावायरस के कारण हुई आंशिक या पूर्ण बंदी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा लोगों की आवाजाही पर लगी सख्त पाबंदी और सामाजिक दूरी बनाए रखने की मजबूरी ने भारत पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 24 मार्च को ऐलान किया कि अगले 21 दिन तक देश भर में पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) रहेगी। कोरोनावायरस पर काबू पाने का कोई चिकित्सकीय इलाज नहीं खोजे जाने तक आशंका इसी बात की है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वास्तविक संदर्भों में पांच फीसदी तक या उससे भी नीचे आ जाएगा। इसके पीछे की सोच यह है कि भारत को मौजूदा लॉकडाउन की वजह से कम-से-कम एक महीने का आर्थिक आउटपुट गंवाना पड़ेगा।

इस वायरस के असर से पैदा हुए आर्थिक उदासी के माहौल में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय इक्विटी एवं डेट में अपने निवेश को कम कर दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 के अंत में शुद्ध इक्विटी एवं डेट प्रवाह क्रमश: 7.7 अरब डॉलर और तीन अरब डॉलर था। वहीं 20 मार्च, 2020 तक शुद्ध इक्विटी आवक 3.5 अरब डॉलर तक कम हो चुकी थी जबकि भारी विदेशी निकासी होने से शुद्ध डेट प्रवाह ऋणात्मक 4.2 अरब डॉलर हो चुका था। लिहाजा पिछले तीन महीनों में भारत से शुद्ध एफआईआई पूंजी निकासी करीब 11.4 अरब डॉलर रही। यह काफी हद तक 2008-09 और अगस्त-सितंबर 2013 की पुरानी कहानी का दोहराव है जब विदेशी पूंजी आर्थिक अनिश्चितता की हालत में डॉलर-प्रभुत्व वाले साधनों में एक सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में लगी हुई थी।

साफ है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के स्तर पर सार्वजनिक व्यय को उस स्तर तक बढ़ाना होगा कि भारतीयों, खासकर दैनिक कामगारों की आय में आने वाली तीव्र गिरावट से निपटा जा सके। फंडिंग समर्थन की प्रकृति एवं मात्रा सरकार और पीड़ितों के दुखों को लेकर सजग स्वतंत्र विशेषज्ञों के बीच गहन परामर्श पर आधारित होनी चाहिए। उम्मीद है कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपये का जो राहत पैकेज घोषित किया है वह व्यापक चर्चा के बाद ही लाया गया है। इसमें बैंकिंग, कृषि, परिवहन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय जरूर ली गई होगी।

इसके बावजूद पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा रुपया का मूल्य काफी ऊंचा बना हुआ है। गत 16 मार्च को आरबीआई ने दो अरब डॉलर की बिक्री कर रुपये को समर्थन देने की कोशिश की थी जिसमें छह महीनों के भीतर डॉलर की पुनर्खरीद का प्रावधान भी था। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों के 27 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क जाने के बाद यह माकूल समय है कि अगले 12 महीनों में रुपया प्रति डॉलर 85 रुपये या उससे भी नीचे तक जा सके।

मौजूदा वृहद-आर्थिक अनिश्चितताओं और एक महीने में भारतीय इक्विटी सूचकांकों के करीब 35 फीसदी लुढ़क जाने के बीच येस बैंक के संस्थापक एवं पूर्व सीईओ राणा कपूर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ की घटना जल्द ही भुलाई जा सकती है। यह बात अपने आप में अनूठी है कि येस बैंक ने कपूर के पारिवारिक सदस्यों के स्वामित्व वाली 103 कंपनियों को खुले हाथ से कर्ज बांटे। अनिल अंबानी की कंपनियों को भी इस बैंक से 12,800 करोड़ रुपये के कर्ज दिए जाने की खबरें हैं। गत 19 मार्च को निदेशालय ने येस बैंक से मिले कर्जों के एवज में कपूर को कमीशन दिए जाने की आशंका की पड़ताल के लिए अनिल अंबानी से भी पूछताछ की है।

लोगों की याद्दाश्त बड़ी छोटी होती है और वित्तीय धांधलियों एवं घोटालों के संदर्भ में तो यह बात खास तौर पर सही है। मसलन, सार्वजनिक बैंकों के पिछले पांच साल में हुए पुनर्पूंजीकरण का करदाताओं पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। भारत में बेहतर ढंग से संचालित हो रहे निजी बैंक मसलन एचडीएफसी बैंक का बहुलांश स्वामित्व विदेशी कंपनियों का है, वे पूंजी पर ऊंचा प्रतिफल हासिल करते हैं और बांटे गए कर्जों के प्रतिशत के तौर पर उनकी शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां कम हैं। फिर भी इस परिदृश्य पर विचार करना होगा कि भारत में कुल जमाओं का 90 फीसदी अगर निजी बैंकों के पास रहता है तो कैसे हालात बन सकते हैं? फिलहाल यह अनुपात महज 40 फीसदी है।

येस बैंक के मामले में भी हमने देखा कि जैसे ही किसी बैंक की हालत खस्ता होती है तो जमाकर्ताओं समेत हर तरफ से राहत पैकेज दिए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगती हैं। अगर बैंकों के प्रति जमाकर्ताओं का भरोसा तेजी से कम होता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का है या निजी।

ऐसे हालात में करदाताओं को एकमुश्त अनुदान के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस धारणा की पुष्टि करते हैं। इनमें जी-7 देशों में उपजे 2008 के वित्तीय संकट के बाद उठाए गए कदम भी शामिल हैं। 24 मार्च, 2020 को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने यह घोषणा की है कि वह तमाम सरकारी, गिरवी रखी गई एवं कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए एक बार फिर तैयार है। इसका आकार 2008-09 में फेड रिजर्व की तरफ से वित्तीय प्रणाली में झोंके गए 4 लाख करोड़ डॉलर से भी अधिक हो सकता है। इसके अगले दिन अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने ट्रंप सरकार की तरफ से घोषित 2 लाख करोड़ डॉलर के राहत पैकेज को भी मंजूरी दे दी।

भारत में राजनीतिक कुकृत्यों के अलावा वरिष्ठ लोकसेवकों की मौन स्वीकृति के चलते हमारे सार्वजनिक बैंक दोस्ती एवं संपर्कों के आधार पर कर्ज बांटने को मजबूर होते हैं। हम बोर्ड से इतर विशेषज्ञों को वित्तीय संस्थानों एवं नियामकीय संस्थाओं के प्रमुख के तौर पर नियुक्त करने का सरकार को अधिकार देने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। भले ही सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो जैसे नियुक्ति पैनलों का गठन किया है लेकिन सरकार का मौजूदा चलताऊ रवैया तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कानून में प्रावधान नहीं किया जाता है।

बहुत समय नहीं हुआ जब ललित मोदी-इंडियन प्रीमियर लीग, विजय माल्या- आईडीएफसी, नीरव मोदी- पंजाब नैशनल बैंक, चंदा कोछड़-आईसीआईसीआई बैंक और रवि पार्थसारथि- आईएलऐंडएफएस जैसे वित्तीय घपलों में शामिल लोगों को भारत में निजी क्षेत्र के चमकते सितारे बताया जाता था। इन मामलों के सामने आने के बाद भी कई साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार ने खास कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखकर आश्चर्य नहीं होता है। ऐसे मामलों में समाचारपत्र हरेक महीने के पहले बुधवार को एक सूची प्रकाशित कर ऐसे गंभीर मामलों में हुई प्रगति का ब्योरा देने वाला एक चार्ट प्रकाशित कर सकते हैं। अगर सरकारी एजेंसियों की तरफ से कोई नई जानकारी नहीं दी गई है तो उस मामले में शून्य प्रगति दिखानी चाहिए।

सार रूप में कहें तो लोग वही सरकार पाते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। सरकारें ही आरबीआई एवं सेबी और दूसरे वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति करती हैं। हमें खुद को एक ऐसी अवाम के तौर पर पेश करना है जो सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व के बीच के भ्रामक भेद के बजाय अपनी चुनी हुई सरकारों को उनकी नियुक्तियों के लिए जवाबदेह ठहराती है।

(लेखक पूर्व राजदूत एवं विश्व बैंक अधिकारी हैं)

कोरोनावायरस महामारी के बीच निजता का प्रश्न

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

कोरोनावायरस महामारी के बीच सूचना तकनीक तथा कृत्रिम मेधा (एआई) का कई तरह से उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने प्रभावित लोगों की पहचान करने, क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी करने, अहम स्थानों की खोज करने और बड़े स्तर पर डेटा विश्लेषण करने के उद्देश्यों से एआई एल्गोरिद्म तैयार किए हैं। लोगों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए कई देशों की सरकारों ने कई ऐप जारी किए हैं। कारोबारी स्तर पर घर से काम करने की आवश्यकता के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन बढ़ रहा है। कई लोग दोस्तों से बात करने के लिए भी इससे संबंधित ऐप का उपयोग कर रहे हैं।

हालांकि निजता तथा सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से जुड़े लाभ, हानि जैसे अहम सवाल एक लंबे वाद-संवाद का हिस्सा हैं। हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारी जरूरतें क्या हैं? इसलिए जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आती है तो आपको अपनी जरूरतें परिभाषित करनी चाहिए। इसके बाद इंटरनेट पर विभिन्न समीक्षाओं को पढ़ने एवं विश्लेषण करने के बाद ही किसी ऐप का चयन करना चाहिए।

अगर आपको केवल दूरदराज बैठे अपने घर-परिवार वालों या दोस्तों के साथ बातचीत करनी है तो आपको ऐसे ऐप की जरूरत नहीं है जो 250 लोगों को एक साथ वीडियो कॉलिंग की सुविधा देता हो। आपको वह बातचीत रिकॉर्ड भी नहीं करनी है। हालांकि कर्मचारियों तथा ग्राहकों से बातचीत करने वाले कारोबारियों को ऐसी कुछ खासियतों की जरूरत होगी जिसमें छोटी-बड़ी डिजिटल फाइलें भेजने के विकल्प भी शामिल हों। प्रत्येक उपयोगकर्ता गोपनीयता तथा निजता चाहता है। सुरक्षा का पहला स्तर तो ऐप ही है जिसमें हैक होने जैसी खामियां नहीं होनी चाहिए। अधिकांश ऐप आपको मोबाइल फोन के स्टोरेज, माइक, कैमरा और कई तरह के बदलाव करने जैसी अनुमति ले लेते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर प्रदाताओं को डेटा चोरी नहीं होने से जुड़ी प्रतिबद्धताएं देनी चाहिए। डेटा को किसी सुरक्षित सर्वर पर रखना चाहिए।

सॉफ्टवेयर प्रदाता को उपयोगकर्ताओं से जुड़ा डेटा नहीं बेचने से संबंधित अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जूम एक लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता है और फेसबुक को ग्राहक संबंधी डेटा बेचने के आरोप में इस पर कार्रवाई की गई है।

जब सरकार द्वारा जारी किए गए प्लेटफॉर्म की बात आती है तो कई दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं। कई बार उपयोगकर्ताओं के पास विकल्प नहीं होते और उन्हें संबंधित ऐप इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वास्तव में जो ऐप आपकी लॉन्टेक्स सूची साझा कर रहा है, वह एक निगरानी ऐप है।

ये ऐप उपयोगकर्ताओं की स्थिति तथा डेटा को ट्रैक करते हैं। चिकित्सा संबंधी आंकड़ों जैसे कई अहम डेटा का प्रसंस्करण करके उन्हें कई तरह से एक जगह सहेज लिया जाता है। इन ऐप के लिए ब्लूटूथ तथा जीपीएस को ऑन करना भी जरूरी होता है जिससे गोपनीयता तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं तथा हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है।

'इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट' जैसे कुछ ऐप अपराधियों की निगरानी के लिए बनाए गए हैं। ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद वस्तुविशेष की स्थिति, दिशा, यात्रा की गति, दिन विशेष की रियल टाइम गतिविधियों आदि पर नजर रखी जा सकती है। इन आंकड़ों को रियल टाइम में डाउनलोड किया जा सकता है जिसका बाद में विश्लेषण किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा जारी ऐप आरोग्य सेतु के लिए चौबीसों घंटे स्थिति तथा ब्लूटूथ को ऑन रखना जरूरी है। ब्लूटूथ के जरिये संबंधित फोन ब्लूटूथ की रेंज में किसी दूसरे फोन को खोजता है। संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई डिवाइस को लैग कर दिया जाता है और ब्लूटूथ के जरिये ऐसी किसी लैग की हुई डिवाइस की खोज की जाती है। इसके अलावा, फोन पर स्थिति ऑन रहती है जिससे संबंधित व्यक्ति या फोन जिस जगहों पर गया हो, उन्हें रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाए। सिंगापुर, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इजराइल आदि इसी तरह के ऐप जारी कर रहे हैं। हालांकि सिंगापुर द्वारा जारी ऐप ओपन सोर्स ऐप है अर्थात इसमें अगर कोई सुरक्षात्मक खामी है तो इसे बहुत जल्दी ढूंढा जा सकता है। जर्मनी, इटली तथा फ्रांस के नागरिक निजता तथा सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित नहीं हैं क्योंकि इस देशों ने यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। जीडीपीआर के तहत नागरिकों से पूछा जाता है कि उनसे संबंधित कौन-सा डेटा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इससे भी अहम बात यह है कि नागरिकों के पास 'राइट टू फॉर्गेट' का अधिकार है अर्थात, व्यक्ति अपने किसी भी डेटा को रिकॉर्ड से हटाने के लिए कह सकता है। संबंधित डेटा का दुरुपयोग करने पर जुर्माना और दूसरे तरह के दंड का भी प्रावधान है। हालांकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोग्य-सेतु ऐप ओपन सोर्स ऐप नहीं है जिसका अर्थ है कि अगर इसमें कोई खामी मिल जाती है तो हैकर इसका उपयोग कर सकता है। साथ ही, भारत में निजी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। हालांकि इससे जुड़ा एक कानून प्रस्तावित है, लेकिन इस मसौदा विधेयक में भी सरकार के पास किसी भी तरह के डेटा को संजोने की शक्ति होगी।

अगर आपको आरोग्य-सेतु ऐप का उपयोग करना है तो इसे इंस्टॉल करने से पहले अपने निजी डेटा को स्मार्टफोन से हटा दें और इसे फैक्टरी रीसेट कर लें। बाद में जब आप इसे फोन से हटाएं तो भी सबसे पहले फैक्टरी रीसेट कीजिए और इसके बाद ही फोन का इस्तेमाल करें। जिस समय ऐप फोन में मौजूद है, किसी भी तरह के निजी डेटा को फोन में रखने से बचें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, निजता का ध्यान रखें।

कानाफूसी

कोरोना एवं प्रोटोकॉल

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के 30 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश की प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पल्लवी जैन गोविल, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निगम के प्रबंध निदेशक और मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना के सीईओ जे विजय कुमार और अतिरिक्त निदेशक संचार, स्वास्थ्य वीणा सिन्हा भी इनमें शामिल हैं। परंतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के भर्ती होते ही कोरोनावायरस से संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी देखने को मिला। नियमों के मुताबिक कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को चुनिंदा अस्पतालों में ही इलाज कराना है लेकिन प्रमुख सचिव ने घर पर ही स्वास्थ्य लाभ लेना शुरू कर दिया। जबकि एक अन्य अधिकारी ने निजी अस्पताल का रुख किया। बाद में हो-हल्ला होने पर उन्हें चयनित अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

विदेशियों की मदद

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने 31 मार्च को भारत में फंसे विदेशी यात्रियों के लिए जो वेब पोर्टल लॉन्च किया था, उसमें कुल 769 विदेशी पर्यटक पंजीकृत हुए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने फंसे हुए विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान एक अमेरिकी महिला बिहार के सुपौल में फंस गई। उधर, उसका बेटा अमेरिका में सर्जरी करा रहा था। पोर्टल के माध्यम से वह दिल्ली पहुंचने में कामयाब रही। इसी प्रकार पोर्टल ने कोस्टारिका के दो नागरिकों को चेन्नई में सर्जरी के बाद मदद पहुंचाई। एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार जो भारत की यात्रा पर आया था वह अहमदाबाद में फंस गया। परिवार में मिर्गी पीड़ित एक सदस्य की दवा समाप्त हो गई तो पोर्टल ने जिलाधिकारी की मदद से उसे औषधि और भोजन मुहैया कराया। उसे स्थानीय परिवहन की सुविधा भी दिलाई गई।

आपका पक्ष

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बेहाल!

भारत सहित विश्व की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्षों से चल रही आर्थिक सुस्ती के बीच अचानक कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन किए जाने से आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। वैश्विक स्तर पर हुए लॉकडाउन के कारण सभी देशों की औद्योगिक, सेवा, कृषि जैसे क्षेत्रों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देश में कंपनियों ने अपने लाखों कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। इससे अमेरिका में बेरोजगारी दर एक माह में ही 4.4 प्रतिशत बढ़ गई है। दुनियाभर में लॉकडाउन के कारण भले कोरोना का खात्मा हो या नहीं, लेकिन वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी का संकट जरूर उत्पन्न हो गया है। ऐसे में आने वाला समय विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल भरा होगा। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों की

अर्थव्यवस्था के लिए स्थितियां और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होंगी। आईएमएफ ने भी आगाह किया है कि 2020 में उत्पन्न हो रहे आर्थिक संकट वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी से भी खतरनाक है। कोरोनावायरस का प्रकोप इसी तरह से बना रहा तो संपूर्ण विश्व के कृषि क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आने वाले समय में देश में कोरोनावायरस और लॉकडाउन से शेयर बाजार भी गिर गए

वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट का खतरा भी मंडराने लगा है जो खाद्यान्न सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही चिंताजनक है।

आकाश सिंह, प्रयागराज

बैंकिंग नियमन सख्त करने की जरूरत

बैंकिंग की अवधारणा ही विश्वास पर आधारित है, लेकिन करीब तीन दशक से कई बार बैंकों में उजागर हुए घोटाले ने इस पर कुठाराघात लगाया है। येस बैंक में जहां 2014-15 से 2018-19 के बीच कर्ज की बंदरबाट तीन गुना से ज्यादा बढ़ी तो वहीं इसी समय इसका एनपीए भी लगभग 25 गुना बढ़ गया। पीएमसी में भी क्षमता से ज्यादा कर्ज का वितरण किया गया। पीएमसी संकट के समय कुछ ग्राहकों की पैसे डूबने के भय से मौत भी हो गई। बैंकों के कुछ शीर्ष अधिकारियों, मझधार में डूबती कुछ कंपनियों ने मिलकर आम लोगों की जमा धनराशि का दुरुपयोग किया जिसे बाद में बैंक द्वारा एनपीए घोषित कर दिया। लिहाजा ग्राहकों को अपनी जमा धनराशि को निकलने में फजीहत का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में वर्ष 2018 में लगभग 12,936 बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या कर ली तथा इसी साल 10,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। मुश्किल भरे दौर में जब बैंक के नियम गरीब लोगों के लिए अत्यधिक कड़े और बड़े ओहदे वाले भ्रष्ट लोगों के लिए सरल कर दिए जाते हैं तब अविश्वास की भावना का आना स्वाभाविक है। येस बैंक समस्या में भारत सरकार ने जरूर तत्परता दिखाई और जमाकर्ताओं को जमा राशि पर बीमा बढ़ाया गया। स्टेट बैंक, एलआईसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने मोर्चा संभाला और काफी हद तक समस्या के निदान की स्थिति बनने लगी। लिहाजा भले ही जिम्मेदारी बैंक बोर्ड की हो या रिजर्व बैंक के नियमन की, प्रभावी नियमन को लागू करने की सख्त जरूरत है।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

नई दिल्ली | 8 अप्रैल 2020 बुधवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

लॉकडाउन हटने से बढ़ेगा खतरा

आईसीएमआर का अनुमान है कि कोरोनावायरस बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी

रुचिका चित्रवंशी

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने अनुमान लगाया है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो कोरोनावायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस बीच कोविड-19 से कुल 4,421 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

आईसीएमआर का यह अध्ययन ऐसे वक्त पर आया है जब विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकार से लॉकडाउन अवधि 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि अगर 75 फीसदी लॉकडाउन हटा लिया जाता है, तब एक संक्रमित व्यक्ति 2.5 लोगों को संक्रमित करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, 'लॉकडाउन जैसे उपायों को अपनाना अहम है क्योंकि यह कहा गया है कि सामाजिक दूरी बरतना ही पूरे समाज के लिए टीके का काम करेगा। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हम हमारी मदद करें जिससे कि आपकी मदद हो पाए।'

देश में अब तक कोरोनावायरस से जुड़ी 1,07,007 जांच की जा चुकी हैं

आईसीएमआर का अनुमान

- अगर कोई लॉकडाउन नहीं रहा तो एक संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित हो सकते हैं **406** लोग
- अगर **75** फीसदी लॉकडाउन हटाया जाता है तो एक व्यक्ति के संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं **2.5** लोग

देश में कोरोनावायरस से जुड़े आंकड़े

- **4,421** लोगों में संक्रमण की पुष्टि
- **326** मरीज ठीक हुए

आईसीएमआर ने पहले अनुमान लगाया था कि यूनिट आर-नॉट या आरओ 1.5 और चार तक रह सकता है। आरओ से यह मापा जा सकता है कि एक कोविड संक्रमित मरीज कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है और इस लिहाज से इसका अनुमान था कि 1.5 से चार लोग संक्रमित हो सकते हैं। आर-नॉट एक गणितीय टर्म है जिससे यह अंदाजा मिलता है कि कोई बीमारी कितनी संकामक है। आईसीएमआर के नए अध्ययन में आर-नॉट 2.5 माना गया है। सबसे ज्यादा आर-नॉट में चेचक के मामले में देखा गया जिसका अनुमानित आंकड़ा 10 था। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान एवं संचारी रोगों के प्रमुख रमन गंगखेडकर ने भी मीडिया को बताया कि अब तक कोरोनावायरस से जुड़ी 1,07,007 जांच की जा चुकी हैं। इस जांच में करीब 136 सरकारी प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं और करीब 59 निजी प्रयोगशालाओं को भी इसके परीक्षण की इजाजत दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोनावायरस संक्रमण के विभिन्न स्तरों के मरीजों के प्रबंधन के लिए एक रणनीति भी तैयार की है। हल्के संक्रमण वाले लोगों के लिए कोविड केयर सेंटर का इंतजाम करने के लिए लॉज, हॉस्टल, स्टेडियम का इस्तेमाल किया जाएगा और जिन जगहों पर संक्रमित लोगों को अलग रखा गया है उसे अपग्रेड किया जाएगा। वहीं मध्यम स्तर के संक्रमण के लिए ऑक्सीजन आदि की सुविधा वाला एक विशेष कोविड स्वास्थ्य केंद्र तैयार किया जाएगा जिसमें संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रवेश और निकास की अलग जगह होगी। गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को विशेष कोविड अस्पताल में रखा जाएगा जहां आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा होगी।

मैसेज फॉरवर्ड करने पर व्हाट्सऐप हो रहा सख्त

कोरोनावायरस से जुड़ी फर्जी खबरों का प्रसार रोकने के लिए व्हाट्सऐप ने उठाए कदम

नेहा अलावधी

फर्जी तथा भ्रामक खबरों का प्रसार रोकने के लिए मंगलवार को व्हाट्सऐप ने कहा कि वह मैसेज फॉरवर्ड करने पर लगाम लगाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च कर रही है। इसके तहत अगर एक बार कोई मैसेज पांच लोगों या समूहों को फॉरवर्ड किया जा चुका है तो इसके बाद उसे एक बार में केवल एक व्यक्ति या समूह को ही फॉरवर्ड किया जा सकेगा।

भारत में व्हाट्सऐप के 40 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। कंपनी अपनी बीटा रिलीज के आंकड़ों का भी अध्ययन कर रही है, जिसमें किसी संदेश के फर्जी होने की संभावनाओं तथा बार-बार साझा हो रहे मैसेज की जांच करने जैसे फीचर शामिल हैं। व्हाट्सऐप ने एक बयान में कहा, 'विचार यह है कि बार-बार फॉरवर्ड किए जा रहे संदेशों के पास एक लेंस जैसा आइकन दिखाई देगा जिसकी मदद से उपयोगकर्ता संबंधित संदेश को इंटरनेट पर भेज सकेंगे। इंटरनेट पर इस खबर से जुड़ी अगर कोई भ्रामक खबर की जानकारी है तो वह उपयोगकर्ता को मिल जाएगी। संदेश को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उन्हें जांचने से अफवाहों के प्रसार को कम करने में मदद मिलेगी।'

भारत सरकार ने भी एक बार फिर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही फर्जी खबरों को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में कहा था कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरोनावायरस संबंधी फर्जी खबरों के प्रसार पर रोक नहीं लगा पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सऐप पिछले काफी समय से फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने संबंधी मुहिम चला रही है। जनवरी 2019 में कंपनी ने वैश्विक स्तर पर ही संदेश फॉरवर्ड करने पर सीमा लगा दी थी।

कंपनी ने नई निजता संबंधी सेटिंग जारी की हैं और अब उपयोगकर्ता इसका चयन कर सकेगा कि उन्हें किसी समूह विशेष में कौन व्यक्ति जोड़ सकता है। कंपनी बहुत अधिक या ऑटोमेटेड संदेश भेजने के चलते हर महीने करीब 20 लाख समूहों को प्रतिबंधित कर रही है।

- भ्रामक खबरों का प्रसार रोकने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज फॉरवर्ड करने पर लगाम लगाने के लिए एक नया फीचर जोड़ रहा
- अगर एक बार कोई मैसेज पांच लोगों या समूहों को फॉरवर्ड किया गया है तो इसके बाद उसे एक बार में केवल एक व्यक्ति या समूह को ही फॉरवर्ड किया जा सकेगा
- भारत में व्हाट्सऐप के 40 करोड़ उपयोगकर्ता हैं

कोविड-19 से जुड़ी सही तथा प्रमाणित जानकारियों के प्रसार में मदद करने के लिए व्हाट्सऐप भारत समेत पूरे विश्व में सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

भारत में व्हाट्सऐप ने सरकार के प्लेटफॉर्म माईजीओवी के साथ मिलकर एक 'माईजीओवी कोरोना हेल्पडेस्क' की शुरुआत की है।

देश के कई राज्यों में इस तरह की सेवाएं शुरू की गई हैं। जैसे दिल्ली +91-8800007722, महाराष्ट्र +91-202612739, गुजरात +91-7433000104 । इनकी मदद से उपयोगकर्ता भरोसेमंद तथा प्रमाणित जानकारियां पा सकेंगे जो अंग्रेजी के साथ-साथ उनकी स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध होगी। आने वाले सप्ताहों में इस तरह की कई और हेल्पलाइन शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

मलेरिया की दवा के सीमित निर्यात को मंजूरी

सोहिनी दास

अमेरिकी राष्ट्रपति के अत्यधिक दबाव के बाद भारत ने मंगलवार को कहा कि वह अपने पड़ोसी देशों और इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन के आंशिक निर्यात को मंजूरी देगा। माना जा रहा है कि अमेरिका के अलावा ब्राजील और स्वीडन ने भी भारत से यह दवा मुहैया कराने का आग्रह किया है ताकि वे कोरोनावायरस से जंग लड़ सकें।

इस दवा की भारी अप्रत्याशित मांग को मद्देनजर रखते हुए विनिर्माताओं का कहना है कि रोजाना हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन टैललेट लेने वाले संधिवात गठिया के मरीजों के लिए अब इसे खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन का इस्तेमाल संधिवात गठिया जैसी ऑटो-इम्यून बीमारियों, लूपस और कुछ मधुमेह के मामलों में होता है।

विदेश मामलों के मंत्रालय ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन और पैरासीटामोल (दर्द एवं बुखार की आम दवा) को लाइसेंसी श्रेणी में रखा जाएगा और उनकी मांग की स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा, 'हालांकि स्टॉक होने से हमारी कंपनियां निर्यात के अनुबंध पूरे कर पाएंगी।'

हालांकि यह खबर लिखे जाने तक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की थी।

भारत ने मंगलवार को कहा कि इस महामारी के मानवीय पहलू को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि भारत अपने उन सभी पड़ोसी देशों को उचित मात्रा में पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन खरीदने के लिए लाइसेंस जारी करेगा, जो उस पर निर्भर हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'हम इन आवश्यक दवाओं की उन कुछ देशों को भी आपूर्ति करेंगे, जो इस महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। इसलिए हम इस संबंध में किसी भी अटकल या इस मामले के राजनीतिकरण को खारिज करते हैं।'

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत आग्रह के बावजूद हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन टैबलेट के निर्यात को मंजूरी नहीं देता है तो उन्हें आश्चर्य होगा।

इस बीच विनिर्माताओं का कहना है कि वे बढ़ती मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आईपीसीए लैबोरेटरीज और कैडिला हेल्थकेयर भारत और दुनिया भर में इस दवा की दो सबसे बड़ी विनिर्माता हैं। इनमें कैडिला अमेरिकी बाजार को आपूर्ति करती है। वहीं यूएस एफडीए ने आईपीसीए के संयंत्रों पर आयात अलर्ट हटा दिया ताकि वह इस संकट की घड़ी में दवा का निर्यात कर सके। सूत्रों ने कहा कि हर महीने आसानी से हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन की एक अरब टैलबेट का उत्पादन कर सकती है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा।

दिल्ली में होगी एक लाख लोगों की त्वरित जांच

बीएस संवाददाता

दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5 बिंदु योजना तैयार की है। सरकार ने दिल्ली में 30 हजार सक्रिय कोरोना मरीज होने पर इनके इलाज की तैयारी कर ली है। बड़े स्तर पर जांच के साथ ही इलाज के लिए सरकार अस्पताल, होटल, बैंक्वेट हॉल और धर्मशालाओं को अपने कब्जे में लेगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार दूसरे देशों के अनुभवों से सीखते हुए कोरोना से बचाव के उपाय कर रही है। अभी दिल्ली में कोरोना 525 संक्रमित हैं। सरकार के पास करीब 2,950 बेड उपलब्ध हैं। हालांकि कोरोना के 30,000 मामले आने पर भी इलाज की तैयारी कर ली गई है। इतने मरीज होने पर 8,000 बेड का इंतजाम अस्पतालों में किए जाएंगे। इसके अलावा होटलों के 12,000 कमरे और करीब 10,000 मरीजों के बैंक्वेट हॉल एवं धर्मशालाओं में व्यवस्था की जाएगी। जहां हर तरह की जरूरी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी।

गंभीर रूप से बीमार जैसे मधुमेह, दिल की बीमारी वाले और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के मरीजों को अस्पतालों में रखा जाएगा। संक्रमितों की संख्या 30 हजार पहुंचने पर आवश्यक 400 वेंटिलेटर और 1,200 ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था कर ली गई है। केजरीवाल ने बताया कि सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा के आधार 5 बिंदुओं के आधारित एक योजना बनाई है। जिसमें जांच, उपचार, टीमवर्क, ट्रैकिंग और निगरानी शामिल हैं। सरकार दक्षिण कोरिया की तरह दिल्ली में शुक्रवार से एक लाख रैपिड जांच की जाएगी। कोरोना के हॉटस्पॉट जैसे मरकज के आसपास के क्षेत्र व दिलशाद गार्डन में रैंडम जांच की जाएगी। क्वारंटीन में भेजे गए 27,702 लोगों के फोन नंबर पुलिस को निगरानी के लिए दिए गए हैं। मरकज से निकले 2,000 लोगों के फोन नंबर पुलिस को दिए जा रहे हैं। इन लोगों के बाहर के जिन क्षेत्रों में घूमने की सूचना मिलेगी, उन क्षेत्रों को सील किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरू में पीपीई किट की समस्या आ रही थी। अब केंद्र सरकार ने 27,000 पीपीई किट देने की बात कही है। जिससे फिलहाल यह समस्या दूर हो गई है।

- 30 हजार मरीज होने पर अस्पताल, होटल, धर्मशालाओं को कब्जे में लेकर सरकार करेगी उपचार का प्रबंध
- शुक्रवार से एक लाख लोगों की रैपिड जांच शुरू करेगी सरकार
- मरकज क्षेत्र व दिलशाद गार्डन जैसे हॉटस्पॉट में होगी रैंडम जांच

ग्राहकों की बढ़ती चिंता से परेशान हैं ब्रांड

कैंटर के सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया के तीन सबसे ज्यादा चिंतित देशों में भारत भी शामिल है और ग्राहकों का मानना है कि लंबी अवधि के खर्च पर भी पड़ेगा असर

अरुंधती दासगुप्ता

कोविड-19 महामारी फैलने से देश चिंता और दहशत की ओर बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को कैंटर द्वारा जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ताओं की धारणा में पहले से ही अनिश्चितता का भाव है और देश में आर्थिक संकट के उभरने की आशंका के बीच वायरस का कहर जारी रहने और वैश्विक लॉकडाउन की वजह से ग्राहक चिंताजनक स्थिति से गुजर रहे हैं। इस प्रक्रिया में ब्रांडों के सामने एक बड़ी चुनौती है और उनके सामने हालात के सामान्य होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जब वे उपभोक्ताओं के पास पहुंचेंगे।

देश भर में बंदी के कारण गैर-जरूरी सामान की बिक्री पूरी तरह बंद हो चुकी है

कैंटर के साउथ एशिया इनसाइट्स डिविजन की चीफ क्लाइंट ऑफिसर सौम्या मोहंती कहती हैं, 'मैंने स्थानीय और वैश्विक स्तर का जो भी डेटा देखा है उसमें कोविड-19 का खतरा दुनिया में पूरी तरह टलने के बाद भारत में सबसे बेहतर तरीके से रिकवरी होगी।' सर्वेक्षण में महानगरों और राज्यों की राजधानी या उनके प्रमुख शहरों के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया जिनके लिए मौजूदा स्थिति ने एक अकल्पनीय चुनौती दी है और लोग अपनी जीवन शैली के विकल्पों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हुए हैं। सर्वेक्षण से यह अंदाजा लगता है कि वैश्विक महामारी ने भारत में भी खपत के रुझान को वैसे ही प्रभावित किया है जैसा कि दूसरी जगहों पर हुआ है और सभी जगहों पर लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों और साफ-सफाई से जुड़े उत्पादों को छोड़कर किसी और चीज की खरीदारी नहीं जा रही है और निश्चित तौर पर इस दौर के खत्म होने के बाद आगे की राह काफी अलग होगी। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि उपभोक्ताओं के मानने, कहने और करने में एक बड़ा अंतर होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज रिकवरी का आशावादी नजरिया भी निराशावाद की इस भावना से निकला है कि लोग सबसे बुरी स्थिति के लिए भी तैयार हो रहे हैं जहां भविष्य में ज्यादा कमी के आसार बन सकते हैं। हालांकि उपभोक्ताओं का मानना है कि यह राष्ट्रों के लिए एक अस्थायी झटका है और उनकी खरीद का रुझान एक बड़े दहशत की ओर इशारा करता है।

भारतीय (समृद्ध लोगों की एक खास श्रेणी) दुनिया के अन्य हिस्से में मौजूद इस श्रेणी के मुकाबले ज्यादा सामान रख रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जितना बताया जा रहा है उसके मुकाबले हालात ज्यादा खराब होंगे? मोहंती कहती हैं कि इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि हालात कितने खराब हो सकते हैं लेकिन भारतीय उपभोक्ता अपने रवैये में आशावादी दिखता है लेकिन व्यवहार के स्तर पर इतना आशावादी नहीं है।

इसलिए जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं की धारणा में तेजी दिखने लगेगी लेकिन भारत में यह रिकवरी धीमी गति से आएगी। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारतीय लोग किसी स्थापित वैश्विक नामों वाले ब्रांड के बजाय सस्ते या प्राइवेट ब्रांडों को तरजीह दे सकते हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक लोगों (53 फीसदी) ने कहा कि महामारी के बाद वे कीमत/लागत पर अधिक ध्यान देंगे और लगभग 40 फीसदी ने कहा कि वे उन्हीं ब्रांडों को अब नहीं खरीदेंगे जिन्हें वे पहले खरीदा करते थे।

अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में ब्रांडों को क्या करना चाहिए? सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारतीय उपभोक्ता चाहते हैं कि ब्रांड कोरोनावायरस के खिलाफ संघर्ष का हिस्सा बनें। सर्वेक्षण में लगभग 27 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि विज्ञापनदाता इस संकट से जूझने की काबिलियत को दर्शाएं और सर्वेक्षण में शामिल सभी देशों में भारत ही एकमात्र देश जहां के लोग यह मानते हैं कि विज्ञापनों को एक सकारात्मक नजरिया देना चाहिए।

कोरोनावायरस का असर

- भारत इस वायरस से घबराने वाले तीन शीर्ष देशों में शामिल है। चीन (63 फीसदी) और ब्राजील (60 फीसदी) के बाद 57 फीसदी भारतीयों का कहना है कि वे इस स्थिति से गहरी चिंता में हैं
- बाकी दुनिया की तरह ही ज्यादातर लोग स्वास्थ्य (31 फीसदी) के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी के बाधित होने (45 फीसदी) से ज्यादा चिंतित हैं
- भारतीय उपभोक्ताओं का कहना है कि वे आशावादी हैं लेकिन दहशत की वजह से ज्यादा खरीदारी करने वालों में वे अव्वल हैं। 51 फीसदी उपभोक्ताओं ने कहा कि वे हालात के खराब होने की आशंका की वजह से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। जबकि अमेरिका में ऐसे 33 फीसदी जबकि ब्रिटेन में 22 फीसदी उपभोक्ताओं का ऐसा मानना है
- लॉकडाउन हटाए जाने के बाद जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनमें ऑनलाइन फूड डिलिवरी और लक्जरी वस्तुएं होंगी। हालांकि स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर जोर दिया जाना जारी होगा और सैनिटाइजर के साथ सफाई वाले सामानों में तेजी दिखेगी
- ज्यादातर भारतीय उपभोक्ता बड़े ब्रांडों की खरीदारी से परहेज करेंगे

स्रोतः देश के महानगरों और प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं के व्यवहार पर कोविड-19 का कैसा प्रभाव है, इससे जुड़ा कैंटर सर्वे

सूना-सूना लगता है सबसे व्यस्त स्टेशन

पृष्ठ 1 का शेष

स्टेशन के एक अन्य कर्मचारी राकेश शर्मा प्लेटफॉर्मों पर रहने वाले आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। वह कहते हैं, 'हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे आसपास कोई भी जीव भूखा न रहे। लॉकडाउन से पहले यात्री उन्हें खाना खिला देते थे।' शर्मा ने कहा कि इस समय टिकट, पूछताछ और पार्सल समेत सभी प्रमुख विभाग बंद हैं। शर्मा जहां खड़े हुए हैं, उनसे कुछ कदम की दूरी पर भारतीय रेलवे के कोरोना आइसोलेशन कोच का नमूना नजर आता है। सरकार ऐसे 5,000 कोच बनाना चाहती है, जिनमें करीब 80,000 बेड की क्षमता होगी। गोयल ने कहा, 'सामान्य डिब्बे में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए जा रहे हैं ताकि आइसोलेशन कोच को मरीज के लिए आरामदेह बनाया जा सके।

हमने ओर से बीच वाली सीट (मिडिल बर्थ) हटा दी है और सामने की तीन सीटें भी हटा दी हैं।'आइसोलेशन कोच के बाथरूम और टॉयलेट में बदलाव किया गया है और स्वास्थ्य पेशेवरों के आराम के लिए अलग जगह बनाई गई है। प्रोटोटाइप के मुताबिक प्रत्येक कोच में करीब आठ मरीजों को रखा जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें 16 मरीजों को भी रखा जा सकता है।

रेलवे स्टेशन के बाहर लोग आरपीएफ के खाद्य आपूर्ति काउंटर पर कतार में लगे हैं। आरपीएफ ने यह काउंटर इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और कुछ गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर खोला है। आरपीएफ के सुरक्षा आयुक्त हरीश सिंह पापोला ने कहा, 'हम नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गाजियाबाद समेत दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रोजाना करीब 4,500 लोगों का खाना मुहैया करा रहे हैं। स्टेशन को देखने से पता चलेगा कि बहुत से लोग भूखे हैं। वे अपनी जीविका के लिए पूरी तरह यात्री सेवाओं पर निर्भर थे। हम उन्हें दोपहर और रात का खाना मुहैया करा रहे हैं।'खाना बांटते समय सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। वे खाने के पैकेट लेने से पहले सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते हैं। पापोला ने कहा कि आरपीएफ का पूरे कर्मचारी काम कर रहे हैं क्योंकि माल की सुरक्षा बहुत अहम है। एक बेघर पवन कमार ने आरपीएफ के काउंटर से खाने का पैकेट लेते हुए कहा, 'साबह रेल गाड़ी नहीं है मगर हमें जीवन की गाड़ी तो चलानी ही है।'